



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 2006/श्रावण 23, 1928

No. 191]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 2006/SRAVANA 23, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नयू शिपर समीक्षा संबंधित अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2006

अंतिम जांच परिणाम

विषय : मै. इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) के जरिए मै. हियूआन वैनफेंग सिरेमिक्स कं. लि., चीन जन. गण. (उत्पादक) और मै. फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं. लि., चीन जन. गण. (निर्यातक) द्वारा किए गए अनुरोध पर विट्रीफाइड/पोसिलेन टाइल्स के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की नयू शिपर समीक्षा (नियम 22 के अंतर्गत)

सं. 15/19/2004-डीजीएडी.- वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

## क. प्रक्रिया

1. निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :-

- (i) मै. हियूआन वैनफेंग सिरेमिक्स कं. लि., चीन जन. गण. (उत्पादक) (जिसे एतद्वारा एच डब्ल्यू सी कहा गया है) और मै. फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं. लि. चीन जन. गण. (निर्यातक) (जिसे एतद्वारा ल्यूंगो कहा गया है) ने मै. इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) (जिसे एतद्वारा ई टी कहा गया है) के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी से ए डी नियमों के नियम 22 के तहत पाटन मार्जिन का निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया है।
- (ii) प्राधिकारी को मै. इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) के जरिए मै. हियूआन वैन फेंग सिरेमिक्स कं. लि. चीन जन. गण. (उत्पादक) और मै. फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं. लि. से 4-2-2003 की अधिसूचना सं. 37/1/2001 की "नयू शिपर" समीक्षा शुरू करने का अनुरोध प्राप्त हुआ। उन्होंने इस आशय का घोषणा-पत्र तथा वचन पत्र प्रस्तुत किया था कि वे संबंधित उत्पाद के बारे में पाटनरोधी उपाय के अध्यधीन चीन जन. गण. के किसी निर्यातक/उत्पादक से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्होंने मूल जांच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। प्राधिकारी ने संबंधित नयू शिपर द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रथम दृष्टया जांच की और उसे पाटनरोधी नियम के नियम 22 के उपबंधों के अनुसार समीक्षा शुरू करने के औचित्य हेतु यथोचित पाया।

- (iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मै0 इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) के जरिए मै0 हियूआन वैनफेंग सिरेमिक्स कं0 लि0, चीन जन.गण. (उत्पादक) और मै0 फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं0 लि0, चीन जन.गण. (निर्यातक) द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर पाटनरोधी नियम के नियम 22 के अंतर्गत 25.8.2004 की अधिसूचना सं0 15/19/2004 - डी जी ए डी के तहत न्यू शिपर समीक्षा शुरू की ।
- (iv) उपर्युक्त न्यू शिपर समीक्षा चीन जन.गण. मूल के सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाली विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के आयात के मामले में शुरू की गई थी जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 4/2/2003 के अपने अंतिम जांच-परिणाम सं0 37/1/2001 के तहत निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला था:-
- (क) जांच अवधि के दौरान यू ए ई तथा चीन जन.गण. से विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों की निर्यात कीमत उसके सामान्य मूल्य से कम थी;
- (ख) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (ग) यह क्षति संचयी रूप से यू ए ई तथा चीन जन.गण. से हुए आयातों के कारण हुई है ।
- (v) केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाली विट्रीफाइड औद्योगिक टाइलों से भिन्न यू ए ई तथा चीन जन.गण. से विट्रीफाइड और पोर्सिलेन टाइलों के आयातों पर मूल जांच में 1.5.2003 की अधिसूचना सं0 73/2003-सी.शु. के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 2-5-2002 से पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।
- (vi) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियम के नियम 22 के अनुसार और 1-5-2003 की अधिसूचना सं0 73/2003 सी.शु. को ध्यान में रखते हुए समीक्षा पूरी होने तक मै0 इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) के जरिए मै0 हियूआन वैनफेंग सिरेमिक्स कं0 लि0, चीन जन.गण. (उत्पादक) और मै0 फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं0 लि0, चीन जन.गण. (निर्यातक) द्वारा किए गए विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के सभी निर्यातों के अनंतिम निर्धारण की सिफारिश की थी;
- (vii) वित्त मंत्रालय ने 30 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं0 102/2004-सी.शु. जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा का परिणाम निकाले जाने तक मै0 हियूआन वैनफेंग सिरेमिक्स कं0 लि0, चीन जन.गण. द्वारा उत्पादित और मै0 इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) के जरिए मैसर्स फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं0 लि0, चीन जन.गण. द्वारा निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाली विट्रीफाइड औद्योगिक टाइलों से

भिन्न विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के सभी आयात समीक्षा पूरी होने तक अनंतिम निर्धारण के अधीन होंगे ।

- (viii) इसके अलावा, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 22 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त जांच-परिणामों तथा अधिसूचना सं० 73/2002-सी.शु. दिनांक 1-5-2003 पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त समीक्षा का परिणाम निकाले जाने तक मै० हियूआन वैनफैंग सिरेमिक्स कं० लि०, चीन जन.गण. (उत्पादक) द्वारा विनिर्मित और मै० एंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) के जरिए मै० फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं० लि०, चीन जन.गण. द्वारा निर्यातित विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के निर्यातों पर, जब उनका आयात भारत में किया गया हो, कोई पाटनरोधी शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा तथा आगे यह प्रावधान किया कि आयातित संबद्ध वस्तु अनंतिम निर्धारण के अधीन रहेगी और 1/5/2003 की अधिसूचना सं० 73/2003 - सी.शु. के तहत संगणित पाटनरोधी शुल्क की राशि के लिए गारंटी प्रदान की जाएगी ।
- (ix) प्राधिकारी ने न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के बारे में निर्यातक देशों के प्राधिकारियों को सरकारी तौर पर सूचित किया और संबंधित सभी हितबद्ध पार्टियों को जांच अवधि (अर्थात् 1 सितम्बर, 2004 से 28 फरवरी, 2005 तक) की समाप्ति से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।
- (x) प्राधिकारी ने संगत सूचना मंगाने हेतु मै० हियूआन वैनफैंग सिरेमिक्स कं० लि०, चीन जन.गण. (उत्पादक), मै० फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं० लि०, चीन जन.गण. (निर्यातक), ब्यूरो ऑफ फेयर ट्रेड (बी ओ एफ टी), चीन जन.गण. सरकार को निर्यातक प्रश्नावली तथा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एम ई टी) संबंधी प्रश्नावली की एक प्रति और मै० एंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) को निर्यातक प्रश्नावली की एक प्रति भेजी । प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ समस्त सूचना मांगी और आवश्यकतानुसार सत्यापन किया । प्राधिकारी ने मै० हियूआन वैनफैंग सिरेमिक्स कं० लि०, चीन जन.गण. (उत्पादक), मै० फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं० लि०, चीन जन.गण. (निर्यातक) और मै० एंटरप्राइज ट्रेडिंग, एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का मौके पर सत्यापन किया ।
- (xi) पाटन के निर्धारण हेतु इस न्यू शिपर जांच की अवधि 6 माह अर्थात् 1 सितम्बर, 2004 से 28 फरवरी, 2005 तक की है ।
- (xii) प्राधिकारी ने 3/6/2005 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित में

दायर करने का अनुरोध किया गया था। पार्टियों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां ले लें और उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।

- (xiii) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल अनुरोध करने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई।
- (xiv) \*\*\* यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है। संबंधित हितबद्ध पार्टियों द्वारा कीमत और लागत के बारे में सूचना गोपनीय घोषित की गई थी और प्राधिकारी ने उसे गोपनीय माना था।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल मामले में यथा-निर्धारित विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइल है। विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किसी भी हितबद्ध पार्टी ने कोई तर्क नहीं दिया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलें नियमों के अर्थ के भीतर मै0 इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफ जेड ई, यू ए ई (निर्यातक) के जरिए मै0 हियूआन वैनफेंग सिरेमिक्स कं0 लि0, चीन जन.गण. (उत्पादक) और मै0 फोशन ल्यूंगो सिरेमिक्स कं0 लि0, चीन जन.गण. (निर्यातक) द्वारा निर्यात की जा रही विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के "समान वस्तु" है। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल जांच में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद अर्थात् "विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइल" माना गया है।

#### ग. हितबद्ध पक्षों द्वारा व्यक्त विचार एवं उनकी जांच

##### ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

3. न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:-
- (क) ई टी द्वारा न्यू शिपर समीक्षा का अनुरोध दिनांक 24.7.2004 को किया गया, जबकि यह 25.8.2004 को अस्तित्व में आया। तदनुसार न्यू शिपर समीक्षा के अनुरोध की तारीख को यह अस्तित्व में ही नहीं था। न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत विधि के विरुद्ध थी, क्योंकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष, प्रथम दृष्ट्या भी, कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे वह संतुष्ट हो सके कि न्यू शिपर समीक्षा की शर्तों को विधिवत रूप से पूरा किया गया है।

- (ख) इस दावे के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि मेसर्स एच डब्ल्यू सी मार्च, 2003 से सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न है। एच डब्ल्यू सी द्वारा आवेदन करते समय आवेदन अपने द्वारा कही गई बात के प्रमाण में निगमन प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय शुरूआत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। एच डब्ल्यू सी ने बताया कि टाइलों के उत्पादन हेतु उन्होंने हाल ही में संयंत्र स्थापित किया है। तथापि एच डब्ल्यू सी ने इस बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं दी है कि क्या यह नया संयंत्र है अथवा किसी उत्पादक से अधिग्रहित पुराना संयंत्र है, जो मूल जांच में भी शामिल था।
- (ग) दावे की सत्यता के अभीनिश्चय के लिए प्राधिकारी को उत्पादक एच डब्ल्यू सी, व्यापारी ल्यूंगो तथा निर्यातक ई टी एवं भारतीय ग्राहक के बीच हुई संविदा अथवा "प्लेसमेंट ऑफ आर्डर" उपलब्ध नहीं कराया गया। यह जांच करने के लिए कि क्या आवेदक वास्तव में इस व्यवसाय में हैं अथवा पहले से लगाए गए शुल्क से बचने का प्रयास कर रहे हैं। निर्यात हेतु प्रस्तावित मात्रा की कोई जानकारी प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराई गई।
- (घ) व्यक्तियों की ऐसी कोई सूची जिससे निर्यातक, व्यापारी तथा उत्पादक संबंधित है, उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे प्राधिकारी को संतुष्ट होने अथवा जांच के पूर्व अपेक्षित निर्धारण तक पहुँचने में मदद मिलती।
- (ङ.) ल्यूंगो के व्यापार के कार्यकलापों की प्रकृति अथवा इसकी शुरूआत के समय के बारे में कोई ब्यौरे आवेदन में नहीं दिए गए हैं, तथापि प्रश्नावली के उत्तर में यह प्रकट किया गया था कि यद्यपि उन्हें 2002 में निगमित किया गया था तथापि उन्होंने प्रचालन केवल 2004 में ही शुरू किया था।
- (च) नियम 22 के अनुसार केवल प्रश्नगत निर्यातक देश से निर्यातक पाटन मार्जिन के पृथक निर्धारण के लिए अनुरोध कर सकता है। वर्तमान जांच में, केवल ई टी ही नियम 22 की पूर्व शर्तों को संतुष्ट करने के पश्चात पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण का दावा कर सकती थी। चूंकि व्यापारी तथा उत्पादक सर्वसम्मति से निर्यातक नहीं थे इसलिए एच डब्ल्यू सी अथवा ल्यूंगो दोनों में से प्रत्येक के लिए पाटन मार्जिन का पृथक निर्धारण नहीं किया गया था क्योंकि दोनों में से प्रत्येक ने वस्तु का निर्यात नहीं किया था। पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य, यू ए ई, न कि चीन में प्रचलित घरेलू कीमतों के आधार पर आधारित होगा।

(छ) एच एण्ड आर जॉनसन (इण्डिया) लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट का अभिमत है कि न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत से पूर्व निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट किया जाना अपेक्षित था कि मूल जांच में दुरुपयोग की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए न्यू शिपर निर्यातक देश में किसी उत्पाद अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं था ।

(ज) नियम 22 के अनुसार किसी न्यू शिपर से आवेदन प्राप्त होने पर हर बार न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत का मामला नहीं बन सकता था । प्राधिकारी न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के लिए वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक अथवा निर्धारित आवधिक समय पर समीक्षा शुरू करने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । वैकल्पिक रूप से, मूल जांच में मूल शुल्क लगाने की अवधि के दौरान अथवा मध्यावधि समीक्षा जांच के दौरान न्यू शिपर की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए थी । नियम 22 में किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए, जो न्यू शिपर का दर्जा हासिल करना चाहता है, वैयक्तिक पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करने का प्रावधान है । "आवधिक समीक्षा" शब्द से यह सूचित होगा कि ऐसे न्यू-शिपर के लिए समीक्षा आवधिक रूप से होनी चाहिए और न्यू शिपर के लिए यह आवधिक रूप से की जानी चाहिए । अन्य शब्दों में नियम 22(2) के तहत किए गए आकलन को निर्दिष्ट प्राधिकारी की आवधिक संस्तुति के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है । तत्पश्चात नियम 22(2) के तहत निष्पादित बॉण्डों और बैंक गारंटियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण तथा संस्तुति के आधार पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्गत कर दिया जाता है अथवा भुना लिया जाता है ।

4. घरेलू उद्योग ने कहा है कि चीन एक "गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश" है और मूल जांच में भी इसे यही माना गया है । अधिसूचना सं. 28/2001-सी.शु.(एमटी) में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों में सूचीबद्ध किया गया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के पैरा 8 के सिद्धांतों के स्थान पर उक्त नियमावली के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांत लागू कर सकते हैं । एचडब्ल्यूसी ने एनएमई प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया और केवल व्यापारी लुंगो के एनएमई उत्तर को संलग्न कर दिया । लुंगो ने नये प्रारूप में एनएमई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया और पुराने प्रारूप में ही एनएमई प्रश्नावली के उत्तर दिए । पुराने प्रारूप के अनुसार भी चीन जन.गण. के व्यापारी लुंगो का एनएमई उत्तर कम और अपूर्ण था । लुंगो ने सम्बद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादक द्वारा प्रभारित कीमत के निर्धारण के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई ।

5. जहां तक गोपनीयता का प्रश्न है, घरेलू उद्योग ने कहा है कि उत्पादक, व्यापारी तथा निर्यातक ने अपने उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है; कि उन्होंने कतिपय दस्तावेजों के संबंध में गोपनीयता के दावे के कारण प्रस्तुत नहीं किए हैं; कि इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि वह जानकारी, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है और ऊपरी तौर से अनुमति दी गई है, संक्षिप्तिकरण हेतु अनुकूल नहीं है । आवेदकों में निम्नलिखित के गोपनीय होने का दावा किया है :-

(i) उत्पाद विवरण पत्र गोपनीय रखे गए हैं । लेखा परीक्षित खाते गोपनीय रखे गए हैं । उनके उत्तर में गोपनीयता बरतने के कोई कारण नहीं बताए गए हैं । लेखांकन पद्धति की विशेषताओं का ब्यौरा नहीं दिया गया है और उन पर किसी प्रकार की गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता था । भारत को की गई बिक्री के मामले में सृजित/प्राप्त दस्तावेजों के पूर्ण सेट का गैर-गोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

(ii) मूल्यहास की दर तथा परिसम्पत्तियों की औसत उपयोगी आयु भी गोपनीय रखी गई है। भवनों, संयंत्र व मशीनरी तथा अन्य परिसम्पत्तियों में किए गए निवेश के संबंध में सूचीबद्ध जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(iii) एचडब्ल्यूसी के परिशिष्ट -1 तथा 2 का समुचित गैर-गोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराया गया है। उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन चक्र काल आदि के ब्यौरे पर गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता। कच्चे माल की सूची भी गोपनीय रखी गई है। परिशिष्ट 8क की जानकारी भी सार्थक तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई है और इसे इस प्रकार से सूचीबद्ध भी नहीं किया गया है, जिससे इसकी विषयवस्तु युक्तियुक्त प्रतीत हो।

(iv) ईटी के एकमात्र प्रोप्राइटर का नाम भी गोपनीय होने का दावा किया गया है और इस दावे के समर्थन में कोई कारण भी नहीं बताए गए हैं। स्थायी परिसम्पत्तियों में किए गए निवेश के संबंध में कोई सूचीबद्ध जानकारी नहीं दी गई है। मूल्यहास दर तथा स्थायी परिसंपत्तियों का जीवनकाल भी नहीं दर्शाया गया है। भारत को की गई बिक्री के मामले में सृजित/प्राप्त दस्तावेजों के पूर्ण सैट का गैर-गोपनीय पाठ उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनकी कम्पनी का ई-मेल पता भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(v) सामान्य भाग के प्रश्न सं. 4 के उत्तर में आवेदक ने बताया है कि निर्यात बिक्री पर कोई विशेष प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुए। तथापि उन्होंने निर्यातों पर वैट की वापसी का दावा किया है। भारत सहित सभी देशों में स्थित अनुषंगी कम्पनियों तथा अन्य संबंधित कम्पनियों, जो संबंधित उत्पाद के विनिर्माण में संलग्न हैं, के नाम, पते, दूरभाष नं. फ़ैक्स नं. आदि के संबंध में सामान्य भाग के प्रश्न सं. 5 का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न सं. 4 के उत्तर में संबंधित व्यक्ति के ई-मेल पते, नाम तथा पदनाम की जानकारी नहीं दी गई है। उत्पादक ने प्रश्न 9 में यथापेक्षित तरीके से लागत लेखांकन पद्धति का विवरणात्मक ब्यौरा नहीं दिया है।

(vi) उत्पादक एचडब्ल्यूसी का परिशिष्ट I दर्शाता है कि सौदा-दर-सौदा ब्यौरे की 414 लाइनें थीं, जबकि व्यापारी लुंगो के उत्तर में सौदा-दर-सौदा ब्यौरे में मात्र 172 लाइनें दर्शाई गई हैं।

(vii) उत्पादक ने न्यूजीलैंड के बारे में परिशिष्ट 3ग में निर्यात कीमत की जानकारी दी है, परंतु इसी परिशिष्ट में अन्य देशों की निर्यात कीमत की कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि भारत को छोड़कर अन्य देशों की निर्यात कीमत की जानकारी दी जानी अपेक्षित है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 6 में अपेक्षित जानकारी चीनी भाषा में दी गई है, जिस पर कोई टिप्पणी करना असम्भव है।

(viii) लुंगो ने प्रमुख शेयरधारक के नाम व उनके द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत गोपनीय रखा है। नाम और प्रतिशत गोपनीय नहीं रखे जा सकते, यदि वे कीमत तथा कम्पनी की लागत से संबंधित न हों और यह जानकारी वाणिज्यिक दृष्टि से संवेदनशील न हो। उन्होंने कहा है कि भारत तथा अन्य देशों को निर्यातित वस्तुएं समान हैं और ऐसे दावे के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने परिशिष्ट 3 में निर्धारित प्रारूप में माह-वार जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने भारत को छोड़कर अन्य देशों को किए गए निर्यात की देश-वार जानकारी प्रदान नहीं की है।

(ix) ईटी ने अपने प्रमुख कार्यालय का पता, दूरभाष नं., फ़ैक्स नं. तथा ई-मेल पता नहीं बताया है और मात्र पी.ओ. बॉक्स नं. दर्शा दिया है। उनके स्वयं के आवेदन के अनुसार उन्हें 24 जुलाई, 2004 को एक आर्डर मिला था, जिसे वे व्यापारी तथा उत्पादक के संयोजन से निष्पादित करना चाहते थे; परंतु ईटी 25 अगस्त, 2004 को अस्तित्व में आया + उन्होंने भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का विवरण अथवा

विनिर्देशन प्रस्तुत नहीं किए हैं। ईटी ने अपने सामान्य वित्तीय लेखा वर्ष का ब्यौरा नहीं दिया है और लेखा परीक्षित खाते की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई है।

(x) न्यू शिपर समीक्षा का आवेदन दिनांक 10 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया गया। आवेदन प्रस्तुत करते समय अर्थात् 23 जुलाई, 2004 को ईटी अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि उनकी स्वयं की स्वीकृति के अनुसार वह दिनांक 24 जुलाई, 2004 को अस्तित्व में आया। आवेदकों ने प्राधिकारी को भ्रमित करके यह विश्वास दिलाया कि वर्तमान मामले की शुरुआत से पहले ही ईटी विभिन्न प्रकार की टाइलों के आयात, निर्यात तथा वितरण के व्यवसाय में संलग्न था। यद्यपि निर्यातक-उत्पादक के लिए संयुक्त रूप से पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई रोक नहीं है, तथापि जिस तथ्य पर ध्यान देना अपेक्षित है वह यह है कि निर्यातक यूएई में है; अतः ईटी हेतु वैयक्तिक पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य यूएई में प्रचलित घरेलू कीमतों पर आधारित होगा, न कि चीन जन.गण. में।

(xi) प्रकटीकरण विवरण की टिप्पणियों पर घरेलू उद्योग ने कहा है कि नियम 22 के अन्तर्गत प्राथमिक शर्त यह है कि न्यू शिपर समीक्षा किसी भी निर्यातक/उत्पादक, जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, से संबंधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि न्यू शिपर से संबंधित सत्ताओं पर, चाहे उन्होंने मूल जांच अवधि में निर्यात न किया हो, शेष पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा और इस प्रकार न्यू शिपर, न्यू शिपर समीक्षा हेतु अनर्ह हो जाएगा। तथापि वर्तमान आवेदन की वैधता निर्धारित करते समय प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षण लागू किया गया है कि निर्यातक अथवा इससे संबद्ध पक्ष द्वारा मूल जांच अवधि की अवधि में निर्यात न किया गया हो, जिसकी कानून के तहत अपेक्षा नहीं की गई है। साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण के पृष्ठ 13(पैरा 7) पर दर्ज दो अनिवार्य शर्तें उपर्युक्त के मद्देनजर अभी भी अपूर्ण रहती हैं; अतः न्यू शिपर आवेदन अस्वीकार करना आवश्यक है।

## ग.॥ निर्यातक/उत्पादक (न्यू शिपर) के विचार

6. निर्यातक/उत्पादक ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :-

(i) आवेदक ने कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाया गया आरोप कि न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन की तारीख को ईटी अस्तित्व में ही नहीं था; सही नहीं है, क्योंकि एसएआईएफ जोन प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2004 को ही अनन्तिम अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था, और अनन्तिम अनुमोदन की प्रति प्राधिकारी को गोपनीय रूप से प्रस्तुत कर दी गई थी। ईटी ने प्रश्नावली के उत्तर में डाक का पूरा पता प्रस्तुत किया है। प्रोप्राइटर का नाम, प्रमाणपत्र तथा प्राधिकार पत्र में दिया गया है, जो ईटी के पत्रशीर्ष में अंकित है [ गैर-गोपनीय उत्तर का पृष्ठ 1 तथा 2 ]। पत्रशीर्ष में यूएई की परम्परा के अनुरूप ई-मेल पते के साथ डाक का पूरा पता दर्शाया गया है।

(ii) यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक नियम 22 में यथापेक्षित तरीके से यह "दर्शाने" में असफल रहा है कि वह न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं। यह आरोप गलत है, क्योंकि तीनों आवेदकों ने अलग-अलग घोषणा पत्र प्रस्तुत किए थे कि उन्होंने मूल मामले में जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था, जिसके अनुसरण में मौजूदा शुल्क लगाए गए और यह कि वे उस निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं, जिनकी वस्तुएं मौजूदा उपायों के अध्वधीन हैं। यदि प्राधिकारी को किस भी संबंध की जानकारी प्राप्त होती है, जो पाटनरोधी नियमावली के प्रतिकूल हो, तो जांच समाप्त की जा सकती है।



(iii) घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि आवेदन के साथ कोई संविदा या आर्डर के रखे जाने संबंधी दस्तोवज संलग्न नहीं थे। आवेदकों का यह अनुरोध है कि आवेदकों के लिए लिखित संविदा या आर्डर में शामिल होना अनिवार्य नहीं था और किसी वैधानिक नियम की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ताओं से ऐसी सूचना प्रदान करने की आशा नहीं की जा सकती जिसे आवश्यक समझा जाता हो। यह आरोप लगाया गया है कि आवेदन के साथ प्राधिकारी के समक्ष ऐसे व्यक्तियों की कोई सूची नहीं प्रस्तुत की गई है जिससे निर्यातक व्यापारी और उत्पादक संबंधित हों। सभी आवेदकों ने घोषणा के रूप में वास्तविक सूचना प्रस्तुत की है। यह आरोप लगाया गया है कि एनएसआर के वर्तमान संयोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य सृजित करने के उद्देश्य से 2004 में व्यापारी और निर्यातक को स्थापित किया गया था। केवल इस तथ्य कि यह कंपनियाँ 2004 के दौरान नई स्थापित थी का यह अर्थ नहीं है कि इनके सृजन का एक मात्र उद्देश्य मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का प्रवंचन है।

(iv) यह आरोप लगाया गया है कि उत्पादक और निर्यातक के बीच बिक्री के लिए संबद्ध वस्तु की कीमत उनके बीच संबंधों से प्रभावित होने की संभावना है। वह कीमत जिसपर भारत में असंबंधित क्रेताओं को इन वस्तुओं को बेचा गया था और कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य संगत थे और न कि संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के बीच की अंतरण कीमत। यह आरोप लगाया गया है कि आवेदन के साथ भारत से प्रस्ताव के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं संलग्न किया है। भारत में इच्छुक आयातकों के नामों की एनएसआर की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ आवश्यकता नहीं है। यह आरोप लगाया गया है कि प्राधिकारी के समक्ष निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्राओं के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है जिनकी अनुपस्थिति में वे आवेदक की "गंभीरता" की जांच नहीं कर सकते हैं। पाटनरोधी नियमावली में यह व्यवस्था नहीं है कि प्राधिकारी तभी जांच शुरू करेंगे यदि मात्राएं अधिक हों या किसी निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक हों।

(v) घरेलू उद्योग का तर्क है कि एचडब्ल्यूसी और लुंगों के संबंध में किसी अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है; और ईटी के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत केवल यूई में प्रचलित सामान्य मूल्य के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है और न कि चीन में प्रचलित सामान्य मूल्य के संबंध में। नियम 22 में जांचाधीन निर्यातक देश के किसी "निर्यातक या उत्पादक" के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की व्यवस्था है। इस मामले में, निर्यातक देश चीन है और न कि यूई क्योंकि भारत को वस्तुओं का नौवहन सीधे चीन जन. गण. से किया गया है। इसके अलावा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क (1)(ग) में सामान्य मूल्य को परिभाषित किया गया है और इसमें "निर्यातक देश या क्षेत्र" का संदर्भ दिया गया है न कि "निर्यातक के देश" का। इसके अलावा, जांचाधीन निर्यात बिक्री सौदों में एक शृंखला है जिसमें "चीनी उत्पादक-चीनी निर्यातक - यूई का निर्यातक" शामिल हैं। तदनुसार, बिक्री की उक्त शृंखला के लिए एक एकल पृथक पाटन मार्जिन की मांग की गई है और न कि शामिल उत्पादक और निर्यातक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन की।

(vi) घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि एनएसआर आवधिक रूप से की जानी चाहिए और न कि जैसे और जब आवेदन प्राप्त हो तब। आवेदक का यह अनुरोध है कि सेस्टेट ने एनएसआर-। से संबंधित अपील में इस मुद्दे का पहले ही निपटान कर दिया है जिसमें यह माना गया है कि एनएसआर को जैसे और जब आवेदन प्राप्त होते हो तभी शुरू किया जाएगा। उक्त निर्णय घरेलू उद्योग के संबंध में पूर्व निर्णय के रूप में कार्य करते हैं।

(vii) एचडब्ल्यूसी ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा पुराने प्रपत्र के अनुसार एनएमई प्रश्नावली का उत्तर अनजाने में प्रस्तुत किया गया है और अगोपनीय अंश में एचडब्ल्यूसी के बजाय लुंगो के उत्तर को लगाया गया है तथापि, इसके बाद एचडब्ल्यूसी और लुंगो ने नए प्रपत्र के अनुसार अपने एनएमई उत्तर के अगोपनीय अंश प्रस्तुत किए हैं।

(viii) आवेदकों ने गोपनीयता के अपने दावे के लिए कारण बताते हुए ब्यौरेवार अनुरोध प्रस्तुत किया है। प्रश्नावली के गोपनीय अंश में सौदा- दर- सौदा आधार पर उत्पादों के आकार, ग्रेड आदि दिए गए हैं और गोपनीयता का दावा भारत को बिक्रियों के मामले में सृजित/प्राप्त दस्तावेजों के संबंध में किया गया है क्योंकि इसमें व्यावसायिक दृष्टि से संवेदनशील सूचना दी गई है जिसमें विभिन्न बाजारों से एचडब्ल्यूसी की पकड़ समाप्त हो सकती है इस प्रकार इनमें गोपनीयता का दावा किया गया है। तत्पश्चात् निवेशों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है। लेखांकन विवरणों संबंधी टिप्पणियों को गोपनीय प्रकृति का माना गया है क्योंकि ये लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में दी गई हैं जिन्हें जनता को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ix) एचडब्ल्यूसी के परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में सौदा- दर- सौदावार ब्यौरे दिए गए थे और इस सूचना का सारांश परिशिष्ट 2क और परिशिष्ट 3 में उपलब्ध कराया गया था। एचडब्ल्यूसी ने परिशिष्ट 1 और 2 में सौदों की संख्या बताई है और सौदावार आधार पर तिथि, मात्रा, उत्पाद कोड, आकार, ग्रेड, निर्यात का देश, संबंध, बीजक संख्या आदि जैसी सूचना व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होती है तथा तदनुसार, इस सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

(x) उत्पादन प्रवाह चार्ट उत्तर के अगोपनीय अंश के पृष्ठ 37 पर पहले ही दिया गया है। एचडब्ल्यूसी द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची में वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील और व्यावसायिक स्वामित्व संबंधी सूचना दी गई है और उनके गोपनीय होने का दावा किया गया है। परिशिष्ट 8क को सूचीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है जो यह दर्शाता है कि कुल लागतों का 0.19% भारत को निर्यातित वस्तुओं की लागत से संबंधित है जबकि अन्य देशों को निर्यातित वस्तुओं की लागत 99.81% है।

(xi) ईटी के एकमात्र मालिक का नाम प्रमाणपत्र में दिया गया है और उत्तर के अगोपनीय अंश के पृष्ठ 1 और 2 में प्राधिकार संबंधी पत्र दिया गया है। बिक्री संबंधी दस्तावेजों को उनके व्यावसायिक दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण गोपनीय माने जाने का दावा किया गया है।

(xii) एचडब्ल्यूसी ने अपने उत्तर में बताया है कि उनके लेखे पूर्णतः चीन के जीएएपी के अनुरूप हैं। प्राधिकारी को गोपनीय रूप से प्रस्तुत लेखा परीक्षित लेखों में यह विशिष्ट प्रमाणपत्र है कि ये लेखे चीनी लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(xiii) एचडब्ल्यूसी लुंगो के अलावा अनेक व्यापारियों को संबंधित उत्पाद की बिक्री करती है। अतः एचडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत सौदावार ब्योरे लुंगो द्वारा प्रस्तुत सौदावार ब्योरों की तुलना में अधिक हैं।

(xiv) अन्य देशों से संबंधित पूरी सूचना परिशिष्ट 2 में प्रस्तुत की गई है और परिशिष्ट 3ग में दी गई सूचना केवल न्यूजीलैंड के संबंध में है क्योंकि न्यूजीलैंड को सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1) के स्पष्टीकरण (ग)(ii)(क) के अर्थ के भीतर उचित तीसरा देश माना गया है।

(xv) लुंगो ने अपने शेयरधारकों के नाम और उनकी शेयरधारिता की मात्रा के बारे में गोपनीयता का दावा किया है लेकिन शेयरधारकों की स्थिति और संख्या का खुलासा किया गया है। लुंगो ने भारत को और तीसरे देशों को हुए निर्यातों की कीमत के बीच कीमत संबंधी तुलना के प्रयोजनार्थ व्यापार की मात्राओं एवं स्तरों के संबंध में किसी समायोजन का दावा नहीं किया है इसलिए ऐसे समायोजनों को प्रमाणित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(xvi) खण्ड 6 के अनुसार, ज्ञापन और ईटी के संस्था के अंतर्नियम के अन्य मामलों, जिनकी एक प्रति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है; पहला वित्तीय वर्ष जुलाई, 2004 में शुरू होगा और मई, 2005 में समाप्त होगा। इसके बाद का वित्तीय वर्ष 12 माह की अवधि का होगा और हर वर्ष मई में समाप्त होगा। यह नोट किया जाए कि ई-2 के अंतर्गत प्रश्न (निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र के वर्णनात्मक भाग में) में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जैसाकि पहले बताया गया है कंपनी की स्थापना जुलाई, 2004 में हुई थी और तदनुसार, पिछले किसी वर्ष का तुलन पत्र नहीं है।

(xvii) चूंकि लुंगो ने द्विभाषी प्रपत्र (अंग्रेजी एवं चीनी) का प्रयोग किया है इसलिए ईटी द्वारा भी उसी द्विभाषी प्रपत्र का प्रयोग किया गया है। ईटी ने कुछ परिशिष्टों के लिए आसानी से द्विभाषी प्रपत्र का प्रयोग किया है, इसलिए यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि ईटी के रिकार्ड चीनी भाषा में रखे जाते थे। ईटी ने केवल भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, इसलिए लाभ निर्धारण आदि में भिन्नताओं का प्रश्न नहीं उठता।

(xviii) आवेदकों का यह दावा है कि जांच अवधि के दौरान न तो उन्होंने और न ही निर्यातक देश में उनके किसी संबंधित उत्पादक या निर्यातक ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। उन्होंने आगे कहा है कि एचडब्ल्यूसी की स्थापना 6 जून, 2001 को और लुंगो की स्थापना 25 जून, 2002 को की गई थी। इस प्रकार आवेदक निर्यातक देश के बाजार में नया प्रवेशकर्ता पाया गया है क्योंकि मूल जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक थी। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

(xix) जैसाकि पाटनरोधी नियमावली और पाटनरोधी करार में उल्लेख है न्यू शिपर समीक्षा का उद्देश्य काफी सीमित है और ये नए निर्यातक/उत्पादक के पाटन मार्जिन के निर्धारण तक सीमित है और अन्य समीक्षाओं की तरह ये क्षति निर्धारण से संबंधित नहीं है। अतः जैसाकि पाटनरोधी नियमावली की भाषा में प्रयोग किया गया है; आवधिक शब्द को छह महीने की अवधि या एक वर्ष की अवधि या ऐसी वस्तुओं पर पाटनरोधी उपायों को लागू करने की तारीख से एक वर्ष होने पर नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 9.5 के केवल पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि तत्काल शब्द का प्रयोग इस इरादे से किया गया है कि जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जांच की शुरुआत तत्काल की जाएगी यदि एक बार वे इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि यह प्रदर्शित करने वाली सूचना मौजूद है कि न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत हेतु निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं। अतः नियम 22 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द आवधिक की व्याख्या उदार ढंग से और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5, जिसमें ऐसी समीक्षा की तत्काल शुरुआत की बात कही गई है, के अनुरूप की जानी चाहिए।

(xx) उन्होंने अनुरोध किया है कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में कतिपय सूचना को गोपनीय मानने की व्यवस्था है। कतिपय सूचना जो या तो व्यापारिक स्वामित्व संबंधी सूचना हो या कोई अन्य सूचना जो गोपनीय प्रकृति की हो, उदाहरणार्थ, क्योंकि उसका प्रकटन किसी प्रतिस्पर्धी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ वाला होगा या उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उस व्यक्ति ने वह सूचना हासिल की है या किसी जांच में जिसे पक्षकारों ने गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया हो, को उचित कारण बताए जाने पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीय ही माना जाएगा। इस एनएसआर में कतिपय व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना जैसे कार्पोरेट संरचना, विपणन एवं बिक्री व्यवस्थाओं, लेखांकन एवं वित्तीय प्रथाओं से संबंधित सूचना संबद्ध उत्पाद के बारे में ब्यौरों और अन्य संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है जिनके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और इससे कंपनी के व्यापार पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वह सूचना जिसका सारांश करना संभव नहीं है, के गोपनीय होने का दावा किया गया है और ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

### ग. III प्राधिकारी द्वारा जांच

7. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए न्यू शिपर समीक्षा शुरू की जो नीचे पुनः प्रस्तुत है:

'नियम 22 : (I) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संदर्भाधीन निर्यातक देश के किन्हीं ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेगा जिसने जांच अवधि के दौरान भारत को उक्त उत्पाद का निर्यात नहीं किया है किन्तु ये निर्यातक या उत्पादक यह प्रदर्शित करते हैं कि वे निर्यातक देश के उन निर्यातकों या उत्पादकों से संबंधित नहीं हैं जिनके संबंध में उक्त उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है।

(2) केन्द्र सरकार इस नियम के उप नियम (1) में उल्लिखित समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से हुए आयातों पर अधिनियम की धारा 9 क की उपधारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी:

परंतु यह कि केन्द्र सरकार अनंतिम निर्धारण कर सकती है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए जाने पर उक्त निर्यातक से गारंटी मांग सकती है और यदि ऐसी किसी समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादकों या निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता है तो वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे मामलों में शुल्क लगा सकती है।"

"नियम 22 में यह स्पष्ट किया गया है कि अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किन विशिष्ट परिस्थितियों में न्यू शिपर जांच की शुरुआत की जा सकती है। प्रश्नगत निर्यातकर्ता देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हों (क) कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया हो; तथा (ख) निर्यातक अथवा उत्पादक यह स्पष्ट करें कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं हैं, जिन पर संबद्ध उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया है। प्रकटन विवरण की टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने उसी तर्क को एक बार फिर दोहराया है कि न्यू शिपर हेतु आवेदन करने वाला आवेदक, उसके लिए प्राधिकृत नहीं है, क्योंकि वे उन निर्यातकों/उत्पादकों से संबंधित हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, चूंकि अवशिष्ट शुल्क चीन के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों पर लगाया जाता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर यह पाया कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है क्योंकि विट्रीफाइड/पोर्सिलेन टाइल्स का उत्पादन एच डब्ल्यू सी द्वारा 6 जून, 2001 के बाद अर्थात् मूल जांच में जांच अवधि के काफी समय पश्चात ही शुरू किया गया तथा वे निर्यातक देश के उन निर्यातकों अथवा उत्पादकों से संबद्ध नहीं हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने समामेलन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर

व्यवसाय शुरू करने का तारीख आंकित है तथा प्राधिकारी ने भी न्यू शिपर के उनके दावे के संबंध में कोई प्रतिकूल कारण नहीं पाया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न्यू शिपर की हकदारी के दावे के संबंध में कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। निर्यातक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि 14 कंपनियां, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध हैं। यह स्पष्ट किया गया था कि 14 कंपनियों में से 2 निवेश कंपनियां, 4 व्यापारिक कंपनियां तथा शेष 8 उत्पादक कंपनियां हैं। 8 उत्पादक कंपनियों में से तीन कंपनियां संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रही थीं तथा वे 31/3/2001 अर्थात् मूल जांच की जांच अवधि के पश्चात् ही अस्तित्व में आई थीं। समूह कंपनियों के उद्यम व्यापार लाइसेंसों की प्रतियां उनके अनुदित रूपान्तर के साथ सत्यापन टीम को उपलब्ध कराई गई थीं। यह नोट किया गया है कि ग्रुप कंपनियों में से किसी कंपनी ने 31/3/2001 के पश्चात् अर्थात् मूल जांच की जांच अवधि के पश्चात् ही निर्यात किया होगा। अतः न्यू शिपर के आवेदक के दावे के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ और इस संबंध में प्राधिकारी के समक्ष कोई वास्तविक साक्ष्य लाया नहीं गया।

8. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या मूल जांच में कंपनी ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत को उत्पाद का निर्यात किया है, न्यू शिपर के रूप में आवेदक की पात्रता के संबंध में उसके दावों की जांच की गई थी। उत्पादक, एच डब्ल्यू सी की स्थापना 6 जून, 2001 में की गई थी और यह दावा किया गया था कि उन्होंने मूल जांच में उल्लिखित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कंपनी के व्यापार लाइसेंस की एक प्रति प्रस्तुत की थी जिसमें स्थापना की तारीख 6 जून, 2001 दर्शाई गई है। टीम ने संयंत्र एवं मशीनरी के अधिग्रहण के संबंध में बीजकों का सत्यापन किया और उसकी प्रतियां प्राप्त की गई थीं। यह पाया गया था कि कंपनी ने संबद्ध उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित उपकरण, उसके समामेलन की तारीख के पश्चात् क्रय किया था। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का मानना है कि न्यू शिपर, मूल जांच में प्रारंभिक जांच अवधि के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकते थे।

9. जांच की प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि मै0 ग्वांगडॉंग न्यू झोंग यूआन सिरैमिक्स कं0 लि0, जो एच डब्ल्यू सी के संबद्ध पणधारकों में से एक है, ने मूल जांच के उत्तर में कुछ सूचना प्रस्तुत की है। यह उत्तर, दिनांक 17 सितम्बर, 2001 के उनके पत्र द्वारा उनके एक आयातक के जरिए प्रस्तुत किया गया था। तथापि यह पाया गया कि उसी जांच में, उक्त पत्र के पश्चात् प्राधिकारी को एक अन्य पत्र भी लिखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्राधिकारी द्वारा जिस अवधि के दौरान जांच की गई थी, उस अवधि में इस कंपनी ने कोई निर्यात नहीं किया था। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह नोट किया गया था कि जिस अवधि की प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ में जांच की गई थी, उस अवधि में एन वाई सी ने न ही किसी समग्री का निर्यात किया था और न ही वर्तमान जांच में उनके द्वारा निर्यात के साक्ष्य पाए गए हैं। आगे यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा मूल जांच के समय प्राधिकारी के समक्ष किए गए दावे के संगत है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एन वाई सी ने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया था। जांच के दौरान प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के किसी निर्यातक तथा उत्पादक, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, के साथ न्यू शिपर के संबंधित होने के

साक्ष्य पाए हैं और न ही कोई साक्ष्य प्राधिकारी के समक्ष लाया गया है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

10. घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि एच डब्ल्यू सी ने अपने इस दावे के समर्थन में कि भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, यह नोट किया गया है कि एच डब्ल्यू सी ने क्रमशः परिशिष्ट 1 तथा 2 के प्रारूप में बिक्री संबंधी सूचना प्रस्तुत की है, जिसमें सौदा-दर-सौदा आधार पर आकारों/ग्रेडों का विवरण दिया गया है। उन्होंने भारत को छोड़कर अन्य देशों को किए गए निर्यातों के संबंध में सौदा-दर-सौदा आधार पर सूचना प्रस्तुत की है, जिसमें देशों के नाम का भी उल्लेख है। एच डब्ल्यू सी तथा ल्यूंगो द्वारा प्रस्तुत उत्तरों में सौदों की संख्या में अंतर के संबंध में यह नोट किया गया है कि एच डब्ल्यू सी ने ल्यूंगो अथवा अन्य किसी चीनी निर्यातक के जरिए जांच अवधि के दौरान किए गए समस्त निर्यात सौदों के विषय में सूचना प्रस्तुत की है जबकि ल्यूंगो ने केवल एच डब्ल्यू सी से संबंधित निर्यात बिक्री के विषय में ही सूचना प्रस्तुत की है। यह नोट किया गया है कि समस्त बिक्री आंकड़ों का सत्यापन किया गया था और सौदों की संख्या के संबंध में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

11. प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच की है कि क्या याचिकाकर्ता "शेल्स" कंपनी का सृजन करके अथवा उत्पाद का एकमात्र एजेंट नियुक्त करके शुल्क से बचना चाह रहे हैं तथा क्या वर्तमान कार्यकलाप का उद्देश्य उन शुल्कों से बचना था जिनकी पूर्व में सिफारिश की गई थी। जांच की प्रक्रिया के दौरान कोई वास्तविक साक्ष्य प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया जिसके आधार पर अन्यथा यह निर्धारित किया जा सके कि याचिकाकर्ता न्यू शिपर समीक्षा के लिए अधिकृत नहीं है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि जांच के प्रारंभ होने से पहले प्राधिकारी को बिक्री संविदा/आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया था। न्यू शिपर ने यह कहते हुए घरेलू उद्योग के तर्क का खण्डन किया है कि भारतीय पाटनरोधी नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच के बाद यह नोट किया गया है कि नियम 22 में न्यू शिपर समीक्षा जांच के अनुरोध पर विचार करने हेतु अपेक्षित मात्रा/परिमाण के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, तथापि नियम 22 का उद्देश्य न्यू शिपर, जिन्होंने मूल जांच की जांच अवधि में निर्यात नहीं किया है तथा जो ऐसे किसी निर्यातक/उत्पादक से संबद्ध नहीं है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करना है। इस मामले में न्यू शिपर ने जांच अवधि के दौरान 3732.48 वर्ग मी. के विट्रीफाइड टाइलों का निर्यात किया है, जिसका हिस्सा कंपनी की संबद्ध वस्तु की कुल बिक्री का 0.186 प्रतिशत बनता है।

12. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निर्यातक ने महत्वपूर्ण सूचना को गोपनीय रखा है जिससे विरोधी हितबद्ध पार्टियां, सूचना को चुनौती देने के अधिकार तथा प्राधिकारी को अर्थपूर्ण निवेदन करने से वंचित रह गई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन, हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। कुछेक सूचनाएं जो या तो व्यापार स्वामित्व संबंधी सूचना है अथवा कोई अन्य

सूचना जो सामान्य रूप से गोपनीय है (उदाहरणतः उसके प्रकटन से किसी विरोधी को उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता हो अथवा उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर अथवा उस व्यक्ति पर जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की हो, अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो) अथवा जिसे पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर जांच हेतु प्रदान किया गया हो और उसे किसी ठोस कारण होने पर ही प्रकट किया जाना हो, उसे प्राधिकारी द्वारा ऐसा ही व्यवहार प्रदान किया जाएगा। ऐसी सूचना को पार्टी की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा। इस समीक्षा जांच में कुछ व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय रखा गया है जैसे कि नैगम संरचना से संबंधित सूचना, विपणन एवं बिक्री व्यवस्थाएं, लेखा एवं वित्तीय पद्धति, संबद्ध वस्तुओं के ब्यौरे तथा अन्य संवेदनशील सूचना, जिसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है तथा कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पणधारक के नाम, शेयरों के प्रतिशत, आपूर्तिकर्ताओं के नामों को गोपनीय माना गया था क्योंकि यदि ये अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्राप्त होते हैं तो व्यापार के लिए संवेदनशील साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार व्यापार साइसेंसों को भी गोपनीय माना गया है क्योंकि इससे अन्य हितबद्ध पार्टियों को अपनी बाजार संबंधी कार्यनीति तैयार करने में अनुचित रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार जांच की गई तथा गोपनीयता के दावे के आधार के संबंध में संतुष्ट होने पर ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय सारांश, सार्वजनिक फाइल में रखा गया है, जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में सभी हितबद्ध पार्टियों के लिए निरीक्षण हेतु उपलब्ध है तथा घरेलू उद्योग ने उसकी प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।

13. घरेलू उद्योग द्वारा की गई नियम 22 की व्याख्या के संबंध में कि याचिकाकर्ता से संबंधित सत्ताओं पर अवशिष्ट पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, जिसके कारण आवेदक न्यू शिपर समीक्षा के लिए पात्र नहीं रह गया है, यह नोट किया गया है कि चूंकि नियम का मानदण्ड अलग-अलग पाटन निर्धारण से संबंधित है न कि अवशिष्ट पाटनरोधी शुल्क से इसलिए तर्क में कोई सार नहीं है। नियम 22 का एक उद्देश्य ऐसे निर्यातक/उत्पादक को रोकना है जिसके व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का आकलन किया जा चुका है और जो निर्यातक/उत्पादक के लिए निर्धारित मौजूदा शुल्क दर से बचने के लिए एक नई कंपनी खोलते हैं। अतः यह प्रतिबंध तब लागू होगा जहां ऐसी संबद्ध कंपनी ने न्यू शिपर समीक्षा के आवेदक की तुलना में मूल जांच में एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्राप्त किया हो। अतः इस बात की जांच की जानी आवश्यक है कि क्या संबद्ध पार्टियों ने मूल जांच की अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यदि घरेलू उद्योग की व्याख्या को स्वीकार किया जाता है तो कोई भी उत्पादक/निर्यातक निजी पाटन निर्धारण के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि उस देश के प्रत्येक निर्यातक/उत्पादक पर सभी अन्य श्रेणियों की तरह मूल जांच में निर्धारित किए अनुसार अवशिष्ट पाटनरोधी शुल्क लागू होगा।



## घ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की जांच और पाटन मार्जिन का निर्धारण

### घ.1 घरेलू उद्योग का विचार

14. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि अधिसूचना सं. 28/2001-सी.शु. (एनटी) के अनुसार चीन को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए और प्राधिकारी तदनुसार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करें। उन्होंने दावा किया कि एचडब्ल्यूसी तथा लुंगो द्वारा प्रस्तुत किए गए एनएमई प्रश्नावली के उत्तर पुराने प्रपत्र में काफी त्रुटिपूर्ण थे, अतः बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी उनके दावे को अस्वीकार कर दिया जाए।

### घ. II निर्यातक/उत्पादक (न्यू शिपर) के विचार

15. निर्यातक/उत्पादक (न्यू शिपर) के विचारों का सार- संक्षेप निम्नानुसार है -

(i) एचडब्ल्यूसी और लुंगो, दोनों ने बाजार अर्थव्यवस्था का दावा किया है और अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। एचडब्ल्यूसी एक पूरी तरह से विदेश स्वामित्व वाला उद्यम था जो चीन के कंपनी कानून के तहत कंपनी के रूप में पंजीकृत था। इसकी स्थापना 6.6.2001 को की गई थी। एचडब्ल्यूसी का 100% स्वामित्व न्यू झोंग युआन ग्रुप कं. लि. नामक एक मकाओ कंपनी के पास था। मकाओ कंपनी का स्वामित्व दो व्यक्तियों के पास था, जिनमें से एक मकाओ का स्थायी निवासी था और दूसरा मकाओ का पासपोर्ट धारक था। कंपनी में सरकार की कोई शेयरधारिता नहीं थी। कंपनी के निदेशक बोर्ड में तीन व्यक्ति शामिल थे- जिनमें से एक मकाओ का नागरिक था तथा शेष दो चीनी नागरिक थे। किसी भी निदेशक को चीनी सरकार अथवा किसी स्थानीय सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा नामित नहीं किया गया था। निदेशक बोर्ड की नियुक्ति केवल कंपनी के शेयरधारकों द्वारा की जा रही थी।

(ii) एचडब्ल्यूसी द्वारा कच्ची सामग्रियाँ बाजार संचालित कीमतों पर खुले बाजार से असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गयी थीं। बाजार मांग के आधार पर एचडब्ल्यूसी तथा उसके आपूर्तिकर्ताओं के बीच कीमतों का निर्धारण अथवा उन पर सहमति होती थी। संबद्ध वस्तु के उत्पादन पर अथवा संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्रियों की खरीद के संबंध में सरकार को कोई नियंत्रण नहीं था। एचडब्ल्यूसी ने ईंधन जैसी अनुप्रयोज्य सामग्री को एक निजी कंपनी से और विद्युत राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक उपभोक्ता कंपनी से खरीदा था। किसी विशेष अथवा सन्निहित दलों के बिना अनुप्रयोज्य सामग्रियों को सामान्य दर पर खरीदा गया था। उन्होंने संबंधित आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा ली जा रही विद्यमान कीमतों पर खपत के पैटर्न के अनुसार भुगतान किया है।

(iii) श्रम का क्रय चीन में खुले बाजार से किया गया था और एचडब्ल्यूसी तथा लुंगो दोनों के पास कर्मचारियों को रखने अथवा निकालने का पूरा अधिकार था। नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि के संबंध में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं था। समय- समय पर कर्मचारियों अथवा कर्मचारी यूनियनों के साथ वेतन- दर पर विचार- विमर्श करने के बाद उसका निर्धारण किया जाता था।

(iv) एचडब्ल्यूसी तथा लुंगो दोनों के पास स्वतंत्र लेखा परीक्षा प्रणाली थी जो चीनी जीएएपी के अनुरूप थी। लेखों से लागत एवं राजस्व प्रदर्शित होते थे। लेखों को प्राप्ति आधार पर रखा जाता था और दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली का अनुपालन किया जाता था। लेखों में अन्य बातों के साथ-साथ (क) नकद में कंपनी की समस्त आय एवं व्यय; (ख) कंपनी के लिए सभी सामग्रियों की खरीद एवं बिक्री (ग) कंपनी की पंजीकृत पूंजी एवं देयताएं और (घ) भुगतान का समय, समायोजन और कंपनी की पंजीकृत पूंजी का हस्तांतरण दर्ज किया गया था। वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन महीनों के भीतर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के बाद वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन हेतु निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होता था। एचडब्ल्यूसी और लुंगो, दोनों के लेखों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष अनुभवी सीपीए द्वारा की जा रही थी और लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा करने के लिए चीनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा मानकों का अनुपालन किया है। लेखा परीक्षकों ने प्रमाणित किया है कि वार्षिक लेख व्यवसाय उद्यमों के लिए लेखा मानकों और व्यवसाय उद्यमों हेतु लेखा विनियमों के अनुरूप हैं।

(v) एचडब्ल्यूसी ने 50 वर्ष की अवधि के लिए उचित पट्टे किराए का अग्रिम भुगतान कर के दिनांक 11.6.2001 को जियानटैंग जनवादी सरकार, डाँगुआन काउंटी, हेयुआन सिटी से 50 वर्ष के पट्टे के आधार पर भूमि का अधिग्रहण किया था। इसी प्रकार की शर्तों पर कंपनी ने वर्ष 2003 में और भूमि का अधिग्रहण किया था। एचडब्ल्यूसी ने दावा किया था कि उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं को अनुप्रयोज्य बाजार कीमतों का भुगतान कर के निजी आपूर्तिकर्ताओं से संयंत्र एवं मशीनें प्राप्त की थीं। एचडब्ल्यूसी ने मशीनों की स्थापना के लिए स्थापना/तैयार करने संबंधी व्यय का भी भुगतान किया था।

(vi) चूंकि एचडब्ल्यूसी और लुंगो की स्थापना क्रमशः वर्ष 2001 और 2002 में की गई थी और उन्होंने बाजार रसे समाप्त अचल सम्पत्तियाँ खरीद ली हैं, अतः इसके पश्चात् गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से किसी विकृति के जारी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(vii) लुंगो का कोई ऋण नहीं है। दिनांक 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार एचडब्ल्यूसी के पास ऋण बकाया है और वर्ष 2004 की शुरुआत में इसका भुगतान कर दिया गया है और जांच अवधि के दौरान कोई ऋण बाकी नहीं थी।

(viii) बाजार में प्रचलित वास्तविक विनिमय दरों का प्रयोग कर के विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा खाते में जमा किया गया था। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अथवा उसे रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

(ix) एचडब्ल्यूसी तथा लुंगो ने कभी कोई वस्तु विनिमय या वापसी व्यापार प्रचालन नहीं किया था। एचडब्ल्यूसी तथा लुंगो दोनों दिवालिया एवं सम्पत्ति कानूनों के अधीन थे जो फर्मों के प्रचालन हेतु कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि कंपनी बाजार अर्थव्यवस्था परिस्थितियों के अनुरूप प्रचालन कर रही है क्योंकि कीमतें तथा लागतें बाजार परिस्थितियों को दर्शाती हैं, अतः कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया जाए और

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुरूप सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए।

### घ. III प्राधिकारी द्वारा जांच

16. सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस धारणा के साथ कार्रवाई की कि ऐसा कोई भी देश जिसे जांच के पूर्व के तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी या किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया या माना गया है, उसे गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ईयू तथा अमरीका जैसे डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने पाटनरोधी जांच में चीन को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। वर्तमान मामले में चीन जन. गण. की जांच गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है।

17. प्राधिकारी ने मै. हैयुआन वानफेंग सेरामिक्स कं. लि., चीन जन. गण. (उत्पादक) तथा मै. फोशान लुंगो सेरामिक्स कं. लि., चीन जन. गण. (निर्यातक) को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली तथा निर्यातक प्रश्नावली भेजी। उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी अपने दावे के समर्थन में उत्तर प्रस्तुत किया और भारत से इतर देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यात के आधार पर, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण का अनुरोध किया क्योंकि उनके घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कोई घरेलू बिक्री नहीं होती है। बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी उनके दावे को ध्यान में रखते हुए उत्तर देने वाले उत्पादक तथा निर्यातक के परिसर में मौके पर सत्यापन किया गया था। चीनी उत्पादक ने इस आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार का दावा किया है कि उनके व्यावसायिक कार्यकलापों राज्य के किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या प्रभाव के बिना, देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान किए बिना, वे बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी सूचना तथा उस उद्योग से संबंधित सरकारी नीति के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए ब्यूरो ऑफ फेयर ऑफ फेयर ट्रेड, वाणिज्य मंत्रालय, चीन जन. गण., को भी एमईटी सामान्य प्रश्नावली भेजी गई थी परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था।

18. पाटनरोधी जांच में चीन जन. गण. के मूल की वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 व 8 के अनुसार किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि -

" गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहाँ यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। "

इसके अतिरिक्त पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में (यथासंशोधित) में यह प्रावधान है कि -

" 8. (1) " गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश " वाक्यांश का अर्थ है कि कोई देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों को लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं । जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है । "

(2) यह कहना परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है ।

तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचवना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है । "

19. यह नोट किया गया है कि उत्तर देने वाले चीनी उत्पादक/निर्यातक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में यथाउल्लिखित सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं ताकि प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों पर विचार किया जा सके कि क्या

(क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;

(ख) ऐसे फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है । खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के ह्रास, अन्य राइट ऑफ, वस्तु विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;

(ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; तथा

(घ) विनिमय दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं -

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसे अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती है । निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं ।

20. स्वामित्व प्रबंधन, नियंत्रण, वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक नीतियों और वित्तीय स्थिति आदि से संबंधित विस्तृत प्रश्न आवेदक को प्रेषित किए गए थे उनके द्वारा दाखिल किए गए जवाबों का यह निर्धारण करने के लिए विश्लेषण किया गया था कि इस बात की तुलना में कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में क्या प्रचलित होगा क्या आवेदक ने चीन की सरकार से कुछ हद तक स्वतंत्रता का प्रयोग किया था। प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के संबंध में आवेदकों से सामान्य और विशिष्ट सूचना की मांग की गई थी:-

- स्वामित्व संबंधी ब्यौरे
- शेयरधारिता की पद्धतियां
- प्रवर्तक/नियंत्रक कम्पनी/कंपनियां
- निर्देशक मंडल के सदस्य उनकी कानूनी दर्जा और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा व्यक्ति/पार्टी।
- कच्ची सामग्री निविष्टियां एवं लागत
- राज्य द्वारा किसी न्यूनतम मजदूरी के अनुबंध की विद्यमानता अथवा अन्यथा तथा यदि उपक्रम बाजार मांग के अनुसार मजदूरी संबंधी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- उत्पादन सुविधाएं एवं लागतें
- ऋण एवं सब्सिडियां
- वस्तु विनिमय व्यापार/पहल व्यापार
- लाभ का वितरण
- दिवालियापन एवं सम्पत्ति कानून
- मुद्रा की दरों का परिवर्तन

21. यह जांच करने के लिए कि क्या संसाधनों के आबंटन और आवेदक के निर्णयों पर किसी हद तक सरकार का प्रभाव अथवा हस्तक्षेप था, चाहे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, आवेदक की स्वामित्व पत्रिका की जांच की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों के दावों/प्रति-दावों को ध्यान में रखा गया था और इस संबंध में ब्यौरों का सत्यापन किया गया था। संघटन, बोर्ड में व्यक्तियों की पहचान, उनके कार्य इन व्यक्तियों द्वारा धारण किए गए अन्य पदों आदि की यह निर्धारण करने के लिए जांच की थी कि क्या इन कंपनियों के प्रबंधन और कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप अथवा भागीदारी थी। प्राधिकारी ने निर्देशिका मंडल के गठन, पर्यवेक्षण बोर्ड, महाप्रबंधक, उनके कार्य एवं शक्तियों, नियुक्ति एवं बर्खास्तगी, नियुक्ति आदि के मामलों में कम्पनी की स्वायत्ता संबंधी प्रावधानों और उस भूमिका पर विश्वास किया जो सरकार अथवा सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाले व्यक्ति/निकाय, यदि कोई हों, इन कंपनियों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अदा करते हैं।

22. एच डब्ल्यू सी चीन के कंपनी कानून के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पूर्ण रूप से एक विदेशी स्वामित्व का उपक्रम था और इसकी स्थापना दिनांक 6.6.2001 को की गई थी। एच डब्ल्यू सी, न्यू झोंग युआन ग्रुप कंपनी लि० नामक एक मकाओ की कंपनी के 100 प्रतिशत

स्वामित्व वाला उपक्रम था। मकाओ कंपनी के मालिक दो अलग-अलग व्यक्ति थे जिनमें से एक मकाओ का स्थायी निवासी था और दूसरा मकाओ का पासपोर्ट धारक था। मकाओ आधारित निवेश कंपनी दो व्यक्तियों की थी और यह मूल जांच की अवधि के दौरान अथवा इस जांच में संबद्ध वस्तुओं की भारत को बिक्री करने में शामिल नहीं थी। एन वाई सी जो एक संबद्ध कंपनी है, पूर्ववर्ती जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रही थी, तथापि कंपनी ने पूर्ववर्ती जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं की थी। आवेदक के इस दावे की जांच की गई थी कि उनसे किसी भी संबद्ध साथी ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है और मूल जांच की जांच अवधि के दौरान निर्यातों का कोई साक्ष्य नहीं पाया था। जहां तक एन वाई सी चीन जन.गण. द्वारा मूल जांच में दिए गए प्रकटन का संबंध है, यह पाया गया है कि वस्तुतः उस जांच अवधि में ही यह स्पष्ट किया गया था कि एन वाई सी ने उस जांच अवधि में भारत को किसी सामग्री की बिक्री नहीं की थी और इस आशय का एक पत्र उस जांच में ही दाखिल किया गया है। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि एन वाई सी ने केवल मूल जांच अवधि के बाद ही निर्यातों के लिए अनुमति प्राप्त की थी, विदेशी अर्थव्यवस्था मंत्रालय एवं व्यापार विभाग द्वारा जारी चीन जनवादी गणराज्य में विदेश व्यापार अधिकारों के साथ उपक्रमों हेतु एन वाई सी के अनुमोदन की एक प्रति उपलब्ध करायी थी।

23. यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने बिजली सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी और पानी किसी निजी कंपनी से खरीदा था। चूंकि बिजली की खरीद सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों से की गई थी इसलिए प्राधिकारी ने उन टैरिफ दरों की जांच की जिन पर कंपनी बिजली प्राप्त कर रही थी। नमूना बीजक एकत्र किए गए थे और कंपनी द्वारा प्रदत्त टैरिफ का विनिश्चय किया गया था। यह पाया गया था कि बिजली और पानी पर प्रभार खपत की पद्धति एवं संबंधित बिजली/जल आपूर्ति कंपनी द्वारा प्रभारित प्रचलित कीमतों के अनुसार लगाए गए थे।

24. जहां तक श्रमिक लगाने का संबंध है, कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने नियोजन संबंधी सभी निर्णय लिए थे। कर्मचारी रखने की पद्धति के संबंध में कंपनी को पूर्ण स्वतंत्रता है और उन्हें अल्पकालिक नोटिस देकर निकाला भी जा सकता है। श्रमिक रखने संबंधी नियम सामान्य तौर पर कंपनी और कर्मचारी द्वारा किए गए श्रम अनुबंध द्वारा विनियमित किए जाते थे। उन्होंने दावा किया कि चीन की सरकार ने आवास, चिकित्सा आदि जैसे कोई लाभ नहीं मुहैया कराए थे, तथापि, कंपनी ने मकान प्रदान किया था और इसकी लागत लेखा बहियों में एक व्यय के रूप में प्रदर्शित की गई थी। तन्खाह का भुगतान प्रत्येक महीने किया गया था जिसमें मूल वेतन और अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन शामिल है, तथापि बीमे और आयकर के संबंध में कटौतियों के लिए दावा किया गया पाया गया है।

25. यह दावा किया गया था कि कच्ची सामग्रियों का क्रय खुले बाजार से किया गया था और सरकार को कच्ची सामग्रियों की खरीद करने अथवा कीमत निर्धारित करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल नहीं पाया गया था। यह भी दावा किया गया था कि प्रमुख कच्ची सामग्रियों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता न तो आवेदक कम्पनियों के साथ और न ही सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों से संबंधित थे। कच्ची सामग्री के कुछेक आपूर्तिकर्ताओं के व्यावसायिक लाइसेंसों का भी सत्यापन किया गया था।

26. दिवालियापन और सम्पत्ति कानूनों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि कंपनी सम्पत्ति अर्जित करने के लिए स्वतंत्र थी। कम्पनी ने दावा किया कि दिवालियापन कानून किसी फर्म पर तब लागू होता है जब कोई फर्म दिवालिया हो जाती है और देयताओं का निर्धारण संबंधी ब्यौरा दिवालियापन कानून के अंतर्गत बनाये गए कानून द्वारा अधिशासित होता है।

27. यद्यपि वर्तमान जांचों में उत्पादक एचडब्ल्यूसी है तथापि, प्राधिकारी ने लुंगो (निर्यातक) को भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार दिए जाने संबंधी दावे की जांच करना उपयुक्त पाया था। कम्पनी के व्यावसायिक लाइसेंस की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि यह कम्पनी एक निजी कम्पनी है और यह 25 जून, 2002 अर्थात् मूल जांच की जांच अवधि के बाद स्थापित की गई थी। वर्ष 2003 और 2004 के लिए लुंगो की वार्षिक रिपोर्टों की जांच के संबंध में यह पाया गया था कि कम्पनी ने अपने लेखों को चीन जन.गण. के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बनाया था और लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल शर्त नहीं लगायी गई थी।

28. एचडब्ल्यूसी न्यू झोंग युआन ग्रुप कम्पनी लि० जो मकाओं में निगमित एक कम्पनी है, द्वारा पूर्णरूप से विदेशी स्वामित्व वाला एक उपक्रम है। यह पाया गया था कि मकाओं कम्पनी के दो अलग-अलग व्यक्ति मालिक थे - उनमें से एक मकाओ का स्थायी निवासी था और दूसरा मकाओ का पासपोर्ट धारक था। जहाँ तक लुंगो का संबंध था, यह गुआंगडोंग न्यू झोंग युआन सिरैमिक कम्पनी लि० (90%) और श्री जेंग ची हांग (10%) के स्वामित्व की थी। पहला शेयरधारक चीन के कम्पनी कानून के अंतर्गत एक सीमित दायित्व कम्पनी के रूप में पंजीकृत चीन की एक कम्पनी थी। प्राधिकारी ने एचडब्ल्यूसी और लुंगो में राज्य के स्वामित्व का न तो कोई साक्ष्य पाया और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इन कम्पनियों में सरकार की भागीदारी को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्राधिकारी ने शेष सभी 12 ग्रुप कम्पनियों के व्यावसायिक लाइसेंसों की भी जांच की थी और शेष 12 ग्रुप कम्पनियों में भी किसी में सरकार के स्वामित्व का कोई साक्ष्य नहीं पाया था।

29. प्राधिकारी ने एचडब्ल्यूसी और लुंगो के निर्देशक मंडल के संघटन की भी जांच की और कम्पनी के निर्णय लेने में सरकार के हस्तक्षेप को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं था। निर्देशक मंडल कम्पनी के सभी प्रचालनात्मक निर्णयों के लिए उत्तरदायी था। एचडब्ल्यूसी और लुंगो की एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुच्छेद XIII के अनुसार निर्देशक मंडल कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण था। बोर्ड, महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति करने, कम्पनी के ज्ञापन एवं अनुच्छेद को पूर्ण करने अथवा परिवर्तन करने, कम्पनी को बंद करने अथवा इसके परिसमापन के संबंध में विचार-विमर्श करने, वित्तीय विवरण, आय और व्यय बजट तथा वार्षिक लाभ वितरण योजना अनुमोदित करने और कम्पनी के महाप्रबंधक द्वारा प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण रिपोर्टों को अनुमोदित करने हेतु निर्णय लेने के लिए भी उत्तरदायी था।

30. एचडब्ल्यूसी संबद्ध वस्तुओं एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था और यह 6.6.2001 को अस्तित्व में आया था। भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2002 में लिया गया था और उसके पश्चात संयंत्र की स्थापना की गई थी। कम्पनी की 6125382 वर्ग मी. की स्थापित क्षमता है और आईपी के दौरान वास्तविक उत्पादन 2287468 वर्ग मी. है। यह पाया गया था कि एचडब्ल्यूसी चीन में संबद्ध अथवा असंबद्ध कम्पनियों के जरिए संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा था जो बदले में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करती थी।

31. प्राधिकारी ने तैयार वस्तुओं की बिक्री अथवा विक्रय अथवा उस मात्रा या कीमतों पर कोई प्रतिबंध नहीं पाया जिन पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री अथवा क्रय अथवा निर्यात किया जा सकता था।

32. यह भी पाया गया था कि लेखों में संयंत्र, मशीनों और अन्य आबद्ध परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन की लागतों को प्रदर्शित किया गया था। यह पाया गया था कि एचडब्ल्यूसी और लुंगो दोनों मासिक लाभ एवं हानि विवरण बनाये हुए थे। यह पाया गया था कि वैट रिटर्नस के साथ मासिक लाभ एवं हानि विवरणों को चीन की सरकार के संबंधित प्राधिकरणों के पास दाखिल किया गया था। एचडब्ल्यूसी ने कोई लाभ अर्जित नहीं किया और इसलिए कोई लाभांश वितरित नहीं किया गया था। लुंगो ने केवल नाममात्र के लाभ अर्जित किए थे लेकिन लुंगो के बोर्ड ने अभी तक लाभांश के वितरण की अनुशंसा नहीं की थी। लुंगो द्वारा दिए गए वैट वापसी के आवेदन पक्ष की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि कम्पनी द्वारा वैट वापसी का दावा किया गया है। यह नोट किया जाता है कि कम्पनी जांच अवधि के दौरान लिए गए अपने संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के लिए 13% वैट वापसी की हकदार है। अतः यह नोट किया जाता है कि कच्ची सामग्रियों, प्रौद्योगिकी की लागत, श्रम, उत्पादन, बिक्री एवं निवेश आदि सहित कीमतों, लागतों एवं निविष्टियों के संबंध में सरकार का कोई खास हस्तक्षेप नहीं पाया गया था।

33. यह पाया गया था कि एसआईटीआई, चीन जन.गण. के जरिए एसआईटीआई इटली से कुछेक उपस्करों का आयात किया गया था। जहां कहीं भी उपस्करों को स्थानीय तौर पर खरीदा गया था वहां यह पाया गया था कि उनकी खरीद भुगतान पर की गई थी। यह पाया गया था कि कम्पनी ने जमीन के मूल्य तथा साथ ही अन्य अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान किया था। कम्पनी के खाते में जमीन के परिशोधन तथा अन्य अचल परिसंपत्तियों के अवमूल्यन पर प्रभारों को दर्शाया गया है।

34. एचडब्ल्यूसी 6.6.2001 को ही अस्तित्व में आई थी तथा अभिलेखित साक्ष्य पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से कोई प्रभाव अथवा विकृतियां नहीं दर्शाता। इसी प्रकार विनियमन व्यापार अथवा ऋणों की प्रतिपूर्ति के जरिए भुगतान से संबंधित कोई साक्ष्य भी नहीं पाए गए थे। यह पाया गया था कि एचडब्ल्यूसी तथा लुंगो, दोनों को संपदा प्राप्त करने के लिए मुक्त पाया गया था। एचडब्ल्यूसी तथा लुंगो ने यह दावा किया था कि दिवालिया कानून उन पर दिवालिया होने की स्थिति में लागू होगा तथा यह पाया गया था कि चीनी संपदा कानून तथा दिवालिया कानून निश्चिततता तथा फर्म के प्रचालनों हेतु स्थायित्व की प्रतिभूति देते हैं।



35. विनिमय दर परिवर्तन को भी उनकी लेखा बहियों से सत्यापित किया गया था तथा यह पाया गया था कि निर्यात धन-प्रेषण को सौदे की तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार चीनी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया। सत्यापन दौरे के समय निर्यात बीजकों के यह देखने हेतु जांच की गई थी कि क्या वसूल की गई राशि को उनकी लेखा बहियों में जमा किया गया था अथवा नहीं। प्राधिकारी का यह अवलोकन था कि विनिमय परिवर्तन प्रचलित दरों पर किये गये थे जो कमोबेश स्थिर थीं।

36. पाटनरोधी नियमावली के अनुबन्ध-1 के पैरा 8(3) के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के चीनी उत्पादकों तथा निर्यातकों के दावे के मुद्दे पर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आलोक में प्राधिकारी इस कम्पनी को बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालनरत मानने को उपयुक्त पाते हैं क्योंकि वे प्राधिकारी को यह दर्शा कर संतुष्ट कर सके कि उत्पादन से संबंधित प्रबंधन तथा नियंत्रण, विपणन तथा कीमत लगाना कम्पनी के प्रबंधन के हाथों में था जो राज्य हस्तक्षेप से स्वतंत्र पाया गया था। उपर्युक्त जांच के अलोक में कम्पनी को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबन्ध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने पर विचार किया गया था।

### सामान्य मूल्य

37. धारा 9क(1) (ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अभिप्राय है :-

(i) उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप यथा निर्धारित निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए अभिप्रेत समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य दौर में तुलनीय कीमत; अथवा

(ii) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य दौर में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो रही हो अथवा जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशिष्ट बाजार संबंधी स्थिति अथवा बिक्री की कम मात्रा हो तब ऐसी बिक्रियां एक उचित तुलना की स्थिति नहीं बनाती, उस स्थिति में सामान्य मूल्य या तो:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश से उपधारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप निर्यात किया गया हो; अथवा

(ख) उपर्युक्त वस्तु की उद्गम के देश में उपधारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागत तथा लाभों के लिए, उपयुक्त वृद्धि के साथ उत्पादन की लागत;

38. प्राधिकारी ने मै0 हेयुआन वानफेंग सिरेमिक्स कं. लि. चीन जन.गण. (उत्पादक) तथा मै0 फोशन लुंगो सिरेमिक्स कं.लि. चीन जन.गण. (निर्यातक) को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1) (ग) के अनुरूप सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी। प्रश्नावली के जवाब में न्यू शिपर ने निर्यातक प्रश्नावली में सूचना दर्ज कराई थी। भारत को निर्यातित विट्रिफाइल टाइलों के स्थान माडलों/आकारों के संबंध में सामान्य मूल्य की गणना के लिए यह देखा गया था कि कम्पनी ने कोई घरेलू बिक्री नहीं की है इसलिए उपयुक्त तीसरे देश को की गई बिक्री की जांच की गई थी क्योंकि

ये निर्यात घाटे पर किए गए थे। तदनुसार, उपयुक्त लाभ मार्जिन के साथ निर्यातक के उत्पादन की लागत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त माना गया था। उन्होंने संबद्ध वस्तु के सभी आकार/माडल/प्रकार के निर्धारित प्रारूप में उत्पादन की लागत को अलग-अलग उपलब्ध कराया है जिनका जांचाधीन अवधि में उत्पादन किया गया है। उत्पादन की तत्व-वार उत्पादन की लागत की भी जांच की गई थी तथा कम्पनी द्वारा रखी गई लेखा बहियों से संकलित किया गया था। उत्पाद के लिए सत्यापित आंकड़ों पर आधारित उत्पादन की लागत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया था। चूंकि यथोचित लाभ हेतु उपयुक्त प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सका अतः उत्पादन की लागत पर 5% की दर को संरचित सामान्य मूल्य के आकलन के लिए उपयुक्त माना गया है।

39. कम्पनी ने जांचाधीन अवधि के दौरान भारत को केवल 600 x 600 आकार की विट्रिफाइल टाइलों का निर्यात किया था। उपर्युक्त विश्लेषित विधि पर आधारित संरचित सामान्य मूल्य \*\*\*\* रेनमिनबी/वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

### निर्यात कीमत

40. प्रश्नावली के जवाब में निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के परिशिष्ट-2 में बीजक-वार/आकार-वार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। निर्यातक ने इसके समर्थन में बीजकों की प्रति भी उपलब्ध कराई है। एचडब्ल्यूसी से लुंगो को वस्तु की बिक्री का उनके मूल अभिलेख से सत्यापन किया गया तथा लुंगो से ईटी को संबद्ध वस्तु के निर्यात का भी सत्यापन किया गया। कम्पनी ने जांचाधीन अवधि के दौरान भारत को 3732.48 वर्ग मीटर विट्रिफाइड टाइलों का निर्यात किया है। परिशिष्ट-3 में निर्यात द्वारा दावा किए गए समायोजनों पर भारत के कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत जानने के लिए विचार किया गया है। ईटी के जरिए लुंगो द्वारा भारत को निर्यात का सत्यापन किया गया है तथा यह पाया गया था कि संबद्ध वस्तु का एफओबी स्तर पर निर्यात किया गया था। यह पाया गया था कि निर्यात बिक्री की समेकित राशि का चीनी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक की सलाह पर वसूली की गई है। संबद्ध वस्तु की कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत \*\*\*\* रेनमिनबी वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

### पाटन मार्जिन

41. उपर्युक्त यथा निर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। यह पाया गया है कि निर्यातक ने संबद्ध वस्तु का इसके सामान्य मूल्य पर निर्यात किया है तथा इसलिए पाटन मार्जिन को नकारात्मक निर्धारित किया गया है।

### ड. अंतिम जांच परिणाम तथा प्राधिकारी की सिफारिशें

42. उपर्युक्त पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:

- i) मै0 हयुआन वानफेंग सिरैमिक्स कं. लि. चीन जन.गण. (उत्पादक) तथा मै0 फोशन लुंगो सिरैमिक्स कं. लि., चीन जन.गण. (निर्यातक) द्वारा उत्पादित ग्वांगडांग चीन. जन.गण. के मैसर्स इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफजैडई, यूएई (निर्यातक) के जरिए भारत को निर्यातित विट्रिफाइड/पोर्सिलेन टाइलों की निर्यात कीमत जांचाधीन अवधि के दौरान इसकी निर्यात कीमत से अधिक है।

ii) इसलिए प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि मै0 हेयुआन वानफेंग सिरेमिक्स कं. लि., चीन जन.गण. (उत्पादक) तथा मै0 फोशन लुंगो सिरेमिक्स कं.लि., चीन जन.गण. (निर्यातक) द्वारा उत्पादित तथा मै0 इंटरप्राइज ट्रेडिंग एफजेडई, यूएई (निर्यातक) के जरिए विट्रिफाइड/पोर्सिलेन टाइलों के आयातों पर जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत आती है, कोई पाटनरोधी शुल्क न लगाया जाए ।

iii) इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के अनुरूप सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लाई जाएगी ।

क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### NEW SHIPPER REVIEW NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2006

#### Final Findings

**Subject:** New Shipper Review (under Rule 22) of Anti-Dumping duty imposed on imports of Vitrified/Porcelain Tiles requested by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter).

**No. 1519/2004-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof,

#### A. PROCEDURE:-

1. The procedure described below has been followed:

(i) M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) (hereby referred to as HWC) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) (hereby referred to as Lungo) through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter) (hereby referred to as ET) requested the Designated Authority for determination of dumping margin under Rule 22 of AD Rules;

(ii) The Authority received a request to initiate a 'new Shipper' review of notification no 37/1/2001 dated 4.2.2003 from M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter). They had filed the declaration and undertaking that they are not related to any of the exporters/producers in China PR subject to the anti dumping measures in force with regard to the product concerned. Furthermore, they have also declared that they have not exported the product concerned during the original period of investigation. The Authority prima-facie examined the application submitted by the New Shipper concerned and considered sufficient to justify the initiation of a review in accordance with the provisions of the Rule 22 of Anti-dumping Rules.

(iii) The Designated Authority initiated the New Shipper Review on the basis of request made by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter) under Rule 22 of AD Rules, vide notification No. 15/19/2004-DGAD, dated 25.8.2004;

(iv) The aforesaid New Shipper Review was initiated in the matter of import of Vitrified/porcelain tiles falling under Chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from China PR where the Designated Authority vide its Final Findings No 37/1/2001 dated 4.2 2003 had come to the conclusion that;

(a) The export price of Vitrified/porcelain tiles from UAE and China PR is below its normal value during the period of investigation;

(b) The Indian industry has suffered material injury;

(c) The injury has been caused cumulatively by the imports from UAE and China PR;

(v) The Central Government imposed anti-dumping duty vide Notification No. 73/2003-Customs, dated 1.5 2003, in the original investigation on imports of vitrified and porcelain tiles from UAE and China PR, other than vitrified industrial tiles, falling under Chapter 69 of Customs Tariff Act, with effect from the date of imposition of the provisional anti dumping duty i.e., 2.5 2002;

(vi) The Authority recommended provisional assessment of all exports of Vitrified/porcelain Tiles made by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter) till the completion of the review in accordance with Rule 22 of AD Rules and having regard to the Notification no.73/2003-Cus dated 1.5.2003;

(vii) Ministry of Finance issued Notification No. 102/2004-Customs, dated 30<sup>th</sup> September, 2004 which inter-alia provided that pending the outcome of the review by the Designated Authority, all imports of vitrified/porcelain tiles, other than vitrified industrial tiles, falling under Chapter 69 of the Customs Tariff Act produced by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR and exported by M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter) would be subjected to provisional assessment till the review was completed;

(viii) Further, in exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of the Rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, the Central Government after considering the aforesaid findings of the Designated Authority, and its notification no.73/2003-Cus 1.5.2003 decided that pending the outcome of the said review by the Designated Authority, no anti dumping duty shall be levied on exports of Vitrified/porcelain Tiles manufactured by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) and exported by M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter) when imported into India & further provided that the imported subject goods shall be subjected to provisional assessment and a guarantee for the amount of duty calculated at per rate of anti-dumping duty vide notification No. 73/2003-Customs, dated 1.5.2003.

(ix) The Authority officially intimated the authorities of the exporting countries of the initiation of the New Shipper Review and gave opportunity to all the interested parties concerned to make their views known in writing within 40 days from the expiry of the POI (i.e. 1<sup>st</sup> September 2004 to 28<sup>th</sup> February 2005).

(x) The Authority sent a copy of exporters questionnaire and market economy treatment (MET) questionnaire to M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR (Producer), M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter), the Bureau of Fair Trade (BOFT), Government of China PR and a copy of exporters questionnaire to M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter) to elicit relevant information. The authority sought and verified all information it deemed necessary for the purpose of determination of dumping margin. The Authority conducted on-the-spot verification of the data furnished by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR (Producer), M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) and M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter).

(xi) The period of investigation in this new shipper investigation is for 6 months i.e. 1<sup>st</sup> September 2004 to 28<sup>th</sup> February 2005 for dumping determination.

(xii) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views verbally in the public hearing held on 3.6.2005. All parties presenting their views verbally were requested to file written submissions of the views expressed verbally. The parties were also advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rejoinders, if any.

(xiii) The Authority made available the public file as per Rule 6(7) to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request.

(xvi) \*\*\*\* in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules. The information concerning prices and costing filed by respective interested parties claimed confidential and the Authority treated these as confidential.

## **B. Product Under Consideration and Like Article**

2. The product under consideration in this investigation is a Vitrified/Porcelain tile as determined in the original case. There is no argument made by any of the interested parties on the product under consideration and like article. It is noted that the Vitrified/porcelain Tiles produced by the domestic industry is 'like article' to Vitrified/porcelain Tiles being exported by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR (Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter) within the meaning of the Rules. In view of the foregoing, the Authority holds that product under consideration in the present investigations is the same as considered in the original investigation i.e., "Vitrified/Porcelain Tiles", classifiable under Chapter 69 of the Custom Tariff Act, 1975.

**C. Views expressed by the interested parties and their examination****C-1. Views of Domestic Industry**

3. The domestic industry raised the following issues with regard to initiation of the NSR:

(a) ET made the NSR request on 24.7.2004 while it came into existence only on 25.8.2004. Accordingly, on the date of making the NSR request, ET was not in existence. Initiation of the New Shipper Review was bad in law as there was no material filed before the Hon'ble Designated Authority even prima facie to satisfy itself that the pre-conditions for new shipper review were duly satisfied.

(b) No evidence was placed in support of the claim that M/s. HWC had been engaged in the production of subject goods since March 2003. HWC could have provided the certificate of incorporation and the certificate of commencement of business in support of its claim at the time of making the application to substantiate what was stated in the application. HWC stated that it had recently set up the plant for producing the tiles. However, HWC did not supply adequate information whether it was a new plant or was an old plant taken over from a producer who was subjected to the original investigation.

(c) No contract or placement of order was provided to the Authority between the producer HWC, the trader Lungo and the exporter ET and the Indian customer to ascertain the genuineness of the claims. No indication about the quantities proposed to be exported was provided to the Authority to examine whether such applicants were serious players in this business or were merely looking for ways and means for circumvention of duties already imposed.

(d) No lists of persons, to whom the exporter, trader and producer are related have been provided which would have helped the Authority to satisfy or reach a determination required to be made prior to initiation.

(e) No details about the nature of activities or time of commencement of business of Lungo were provided in their application, however, it was disclosed in the questionnaire response that though they were incorporated in 2002 and commenced operations only in 2004.

(f) In terms of the Rule 22, only the exporter from exporting country in question could request for a separate determination of dumping margin. In the present investigations, it was ET alone who could have claimed for determination of a separate dumping margin after satisfying the pre-conditions of Rule 22. Since the trader and producer admittedly were not the exporters, no separate determination of dumping margin could be made either for HWC or Lungo as both of them did not export the goods. For the purpose of determination of separate dumping margin for ET, normal value shall be based on the basis of prevailing domestic prices in UAE not in China.

(g) In the case of H&R Johnson (India) Ltd. V. Designated Authority, the CESTAT has held that the Designated Authority was required to be satisfied prior to the initiation of New Shipper Review that the new shipper was not related to any of the producers and exporters in the exporting country in the original investigation keeping in view the possibility of abuse.

(h) As per Rule 22, a case for new shipper review could not be initiated each time as and when an application was received from a new shipper. The authority may decide to initiate cases for new shippers annually or semi-annually or based on a periodical basis fixed by the authority. Alternatively, the new shipper was required to be periodically examined during the tenure of the original duties imposed in original investigations or mid-term review investigations. Rule 22 speaks of periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers who were seeking the status of a new shipper. The words "periodical review" would signify that the review has to be periodical for such new shipper and has to be carried out periodically for such new shippers. In other words, the provisional assessments done under Rule 22(2) are finalized based on the recommendation of the Designated Authority periodically. The Bonds or Bank Guarantees executed under Rule 22(2) would then be either released or encashed by the Customs department based on the determination and recommendation of the Designated Authority.

4. Domestic industry has submitted that China is a "non-market economy country" and has been treated as such in the original investigations. In Notification No. 28/2001-Cus (NT), China PR has been listed amongst the non-market economy countries. The Designated Authority may apply the principles set out in Paragraphs 1 to 6 of the AD Rules instead of the principles in Paragraph 8 of the said Rules. HWC provided no response to the NME questionnaire and merely enclosed the NME response of the trader Lungo. Lungo did not respond to NME questionnaire in the new format and merely filed the NME response in the old format. NME response of the trader Lungo from China PR was highly deficient and incomplete even as per the old format. Lungo did not provide detailed information with respect to the determination of price charged by the producer HWC for the subject goods.

5. With regard to confidentiality, the domestic industry has submitted that the producer, trader and exporter have claimed excessive confidentiality in their response; that they have not disclosed the reasons for claims of confidentiality on certain documents; that there were no reasons provided as to why the information on which confidentiality has been claimed and apparently allowed was not susceptible to summarization. The applicants have claimed the following as confidential:

(i) Product brochures have been kept confidential. Audited accounts have been kept confidential. No reasons for seeking confidentiality have been enclosed with their response. Salient features of the accounting system have not been provided and no confidentiality could have been claimed on them. Notes to Accounts have been kept confidential. No non-confidential version of the complete set of documents generated / received in case of sales to India has been provided.

(ii) The rates of depreciation and the average useful life of assets have been kept confidential. No indexed information with respect to investment made in buildings, plant & machinery and other assets have been provided.

(iii) No proper non-confidential version for appendix 1 and 2 of HWC has been provided. Details regarding production process, production cycle time etc. cannot be claimed confidential. List of raw material has been kept confidential. Information in Appendix 8A has not been provided in a meaningful way and the indexation is also not done in a manner to give reasonable understanding of the contents.

(iv) Name of the sole proprietor of ET has been claimed confidential without any reasons to support such claim. No indexed information with respect to investment made in fixed assets has been given. The depreciation rate and the life of the fixed assets have also not been disclosed. Non-confidential version of the complete set of documents generated / received in case of sales to India has not been provided. The e-mail address of their company has not been provided.

(v) In response to question no. 4 of General part, applicants have stated that no special incentives were received on export sales. However, they would have claimed VAT refunds on exports. No response has been given to question no. 5 of Part A General regarding names, addresses, telephone numbers, fax numbers etc. of all subsidiaries or other related companies in all countries including India which are involved in the manufacture of the product concerned. In response to question no. 4, no email address, name and designation of the concerned person have been provided. The producer has not described in narrative form the cost accounting system at length as required under question No.9.

(vi) Appendix 1 of the producer HWC showed that there were 414 lines of transactions by transaction details whereas the response of the trader Lungo showed only 172 lines of transaction by transaction details.

(vii) Producer has given the information of export price in Appendix 3C with respect to New Zealand only and no information for export price to other countries has been provided in the same appendix whereas as stated above the information regarding export to countries other than India is required to be supplied. The information in Appendix 6 has been provided in Chinese language making it impossible to offer comments.

(viii) Lungo has kept the name as well as the percentage of shares held by the principal share holders as confidential. Names and percentages can not be kept confidential when the same are not related with the price and cost of the company and are not commercially sensitive information. They has stated that the goods exported to India and to other countries are identical and no evidence has been placed in support of such a claim. They did not provide month-wise information in Appendix 3 format. They did not provide country-wise information for exports to countries other than India.

(ix) ET has failed to give the address of its main office, telephone number, fax number and email address and merely given P.O. Box number. On 24<sup>th</sup> July 2004 they had as per their own application received an order which they wanted to execute through the



combination of the trader and producer but ET came into being only on 25<sup>th</sup> August 2004. They not provided any description or specification of the subject goods exported by them to India. ET has not given any details regarding its normal financial accounting year and they have not provided a copy of their audited accounts.

(x) The application for new shipper review was filed on 10<sup>th</sup> August 2004. ET was not in existence at the time of filing of application by them i.e., 23<sup>rd</sup> July, 2004 as they had come into existence only on 24 July, 2004 as per their own admission. The applicants misled the authority to believe that ET was already engaged in the business of import, export and distribution of various types of tiles prior to initiation of the present case. While there is no bar for the determination of dumping margin for the exporter-producer combination, what is required to be seen is that the exporter is in UAE and therefore, for the purpose of determination of individual dumping margin for ET, the normal value shall be based on the basis of domestic prices prevalent in UAE, not in China.

(xi) On the comments to the disclosure statement the domestic industry has submitted that the primary condition under Rule 22 is that the applicant for the New Shipper Review should not be related to any of the exporters/producers subjected to anti-dumping duty. They have further argued that the related entities of the new shipper will be subjected to residual anti dumping duty even if not exported during the original POI, thereby making the new shipper ineligible for a new shipper review. However, while determining the legitimacy of the present application, the Authority has applied the test that the exporter or its related party should not have exported during the period of investigations of the original POI which is not the requirement under the law. At the same time, the two necessary conditions recorded by the Designated Authority on page 13(para 7) of the Disclosure Statement, remains unfulfilled in view of the above, therefore, the application of the new shipper needs to be rejected.

#### **C-II. Views of the exporter/producer (New Shipper)**

6. The exporter/producer have made the following submissions:

(i). The applicant has submitted that the allegation made by the domestic industry that ET was not even in existence on the date of their application seeking initiation of NSR is incorrect as the provisional approval had been granted by the concerned SAIF Zone Authorities on 12<sup>th</sup> July 2004 itself and a copy of the provisional approval had been submitted to the Authority confidentially. ET had furnished complete postal address in the questionnaire response. The name of the proprietor was given in the Certificate and the authorization letter which are in the letterhead of ET [Pages 1 & 2 of non-confidential response]. The letterheads showed the complete postal address in a manner that was customary in UAE along with the e-mail address.

(ii) It has been alleged that the applicants failed to 'show', as contemplated under Rule 22, that they meet the pre-conditions required for initiating a NSR. The allegation is incorrect, as all the three applicants had filed the declaration individually that they had not exported the subject goods during the period of investigation in the original case pursuant to which the existing duties were levied and that they were not related to any exporter or producer whose goods were subjected to existing measures. If the Authority

comes to know of any relationship contrary to the AD Rules, the investigation may be terminated.

(iii) The domestic industry has alleged that no contract or placement of order was annexed to the application. The applicants have submitted that it was not mandatory for applicants to enter into a written contract or order and in absence of any statutory rules, the petitioners could not be expected to provide information that might be considered necessary. It has been alleged that no list of persons to whom the exporter, trader and producer are related have been given to the Authority along with the application. All the three applicants gave the factual information in the form of a declaration. It has been alleged that the trader and exporter were set up in 2004 with the objective of creating evidence to justify present combination of NSR. The mere fact that these companies were 'newly set up' during 2004 did not mean that they were created with the sole objective of circumventing existing anti dumping duties.

(iv) It has been alleged that the price of the subject goods for sale between the producer and exporter might have been affected by the relationship between them. The price at which the goods were sold to unrelated buyers in India and the ex-factory normal value was relevant and not the transfer price between related producer and exporter. It has been alleged that no proof in support of the offer from India was provided with the application. Names of intending importers in India were not required for the purposes of initiating the NSR. It has been alleged that no indication about the quantities proposed to be exported was provided to the Authority in the absence of which they could not examine the 'seriousness' of the applicant. The antidumping rules do not provide that the Authority shall initiate an investigation only if the quantities are substantial or above a certain minimum limit.

(v) The domestic industry has argued that no separate dumping margins can be determined in respect of HWC or Lungo as both of them have not exported the subject goods; and in respect of ET, dumping margin can be determined only with respect to the normal value prevailing in UAE and not in China under Rule 22 of AD Rules. Rule 22 provides for determination of individual margins of dumping for any '*exporters or producers*' in the exporting country in question. In the instant case, the exporting country is 'China' and not 'UAE' as the goods have been shipped directly from China PR to India. Further, Section 9A (1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975 defines 'normal value' and it refers to 'exporting country or territory' and not to 'the country of the exporter'. Further, the export sale transactions in question consist of a channel comprising of 'Chinese Producer – Chinese exporter – UAE Exporter'. Accordingly, a single individual dumping margin has been sought for the said channel of sales and not separate dumping margins for the producer or exporters involved.

(vi) The domestic industry has claimed that a NSR shall be conducted 'periodically' and not 'as and when the applications are received'. The applicant has submitted that CESTAT has already settled this issue in the appeal relating to NSR I in which it has been held that the NSR shall be initiated as and when the applications are received. The said decision acts as 'res judicata' on the domestic industry.

(vii). HWC has submitted that NME questionnaire response was filed by them as per old format inadvertently and, in the non-confidential version the response of Lungo had been attached instead of HWC, however, subsequently, both HWC and Lungo have filed non-confidential versions of their NME responses as per new format.

(viii) The applicants have filed a detailed submission giving reasons for its claim of confidentiality. Confidential version of the questionnaire contains the product sizes, grades, etc on a transaction-by-transaction basis and confidentiality has been claimed in respect of documents generated/received in case of sales to India since it contains business sensitive information which may reveal the HWC's, hold on various markets, hence, claimed confidentiality. Indexed information in respect of investments has since been furnished. Notes to the Accounting Statements are confidential in nature as they are contained in the audited annual accounts, which are not required to be made available to the public.

(ix) Appendix 1 and Appendix 2 of HWC contained transaction-by-transaction details and summary of the information was made available in Appendix 2A and Appendix 3. HWC has indicated the number of transactions in Appendix 1 and 2 and information such as date, quantity, product code, size, grade, country of export, relationship, invoice number, etc on a transaction-to-transaction basis are highly business sensitive and accordingly, confidentiality has been claimed in respect of such information.

(x) Production flow chart has already been given at Page 37 of the non-confidential version of the response. List of raw materials used by HWC contain commercially sensitive and business proprietary information and claimed confidential. Appendix 8A has been filed in the indexed form which shows that 0.19% of total costs relate to the cost of goods exported to India whereas the cost of goods exported to other countries constitute 99.81%.

(xi) Name of the sole proprietor of ET has been given in the Certificate and Authorization letter has been placed at pages 1 and 2 of the non-confidential version of the response. Sales documents were claimed as confidential because of its business sensitivity in nature.

(xii) HWC has stated in its response that its accounts fully comply with the Chinese GAAP. The audited accounts submitted in confidence to the Authority contain a specific certificate that the accounts conform to the Chinese Accounting standards.

(xiii) HWC sells the product concerned to a number of traders other than Lungo. Therefore, transaction-by-transaction details furnished by HWC are larger in number as compared to the transaction-by-transaction details furnished by Lungo.

(xiv) The complete information relating to other countries has been submitted in Appendix 2 and information in Appendix 3 C has been provided only in respect of New Zealand since the producer/trader has considered New Zealand to be an appropriate third country within the meaning of explanation (c)(ii)(a) to Section 9A(1) of the Customs Tariff Act 1975 for the purposes of determining normal value.

(xv) Lungo claimed confidentiality regarding the names and the extent of shareholding of its shareholders but the status and the number of shareholders have been disclosed. Lungo has not claimed any adjustment on account of quantities, levels of trade, etc for the purposes of effecting price comparison between export price to India and to other countries. Since no adjustment has been claimed, the question of substantiating such adjustments does not arise.

(xvi) In terms of clause 6 'other matters' of the Memorandum and Articles of Association of ET, a copy of which has been filed confidentially with the Authority, the first financial year shall commence in July 2004 and will end in May 2005. The successive financial year shall be of 12 months duration ending in May every year. It may be noted that the question under E.2 (in the descriptive portion of Exporters' Questionnaire format) requires submission of audited accounts for the last three financial years. As stated already, the company itself came into existence in July 2004 and accordingly, there are no balance sheets for any previous years.

(xvii) Since Lungo has used a bi-lingual format (English and Chinese), the same bi-lingual format has been used by ET. ET has simply used the bi-lingual format for some of the appendices therefore, it is not justified to say that the records of ET were maintained in Chinese. ET has exported the subject goods only to India, therefore, the question of differences in profit determination, etc does not arise.

(xviii) The applicants have claimed that neither they nor any of their related producers or exporters in the exporting country has made any exports of the subject goods to India during the period of investigation. They have further stated that HWC was established w.e.f. 6<sup>th</sup> June, 2001 and Lungo was established w.e.f. 25<sup>th</sup> June, 2002. Thus the applicant is found to be the new entrant to the market in the exporting country, as the period of original investigation was 1<sup>st</sup> April 2000 to 31<sup>st</sup> March 2001. In support of their claim they filed a certification with regard to the above facts.

(xix) The objective of New Shipper Review as stated in AD Rules and AD Agreement is very limited and confined to determine individual dumping margin of the new exporter/producer and does not deal with the injury determination as in the case of other reviews. Therefore, the term periodic as used in the language of AD Rules can't be construed as a period of six months or a period of one year or so from the anniversary date of imposition of anti-dumping measures on such goods. Further the plain reading of Article 9.5 makes it crystal clear that the word promptly has been used with the intention that initiation should be promptly carried by the investigating authorities once they satisfy themselves that prima facie information exists to show that the conditions set for the initiation of New Shipper Review are satisfied. Therefore, the term periodic used under Rule 22 should be interpreted liberally and in conformity of the Article 9.5 of ADA which calls for prompt initiation of such reviews.

(xx) They have submitted that Rule 7 of Indian Anti-Dumping Rules provides for treating certain information confidential. Certain information which are either business proprietary information or any other information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a

person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. In this NSR, certain business sensitive information has been claimed as confidential such as information pertains to corporate structure, marketing and selling arrangements, accounting and financial practices, details about the subject product and other sensitive information disclosure of which would be of significant competitive advantage to a competitor and would adversely affect the business of the company. The information, which is not susceptible of summarization, has been claimed confidential and adequate reasoning for doing so has been provided to the Authority.

### **C.III. EXAMINATION BY THE AUTHORITY;**

7. The Designated Authority initiated new shipper review keeping in view the provisions of the anti dumping rules, which are reproduced below:

*“Rule 22: (1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product.*

*(2) The Central Government shall not levy anti dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act, on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:*

*Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee form the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of initiation of the review”.*

“Rule 22 clearly specifies the circumstances under which a new shipper investigation can be carried out for the purpose of determination of individual dumping margin. Individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the exporting country in question can be determined provided the following two conditions are satisfied, (a) that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and (b) that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subjected to the anti dumping duties on the product concerned. *In comments to the disclosure statement, domestic industry has once again reiterated the same argument that the new shipper applicant is not entitled since they are related with the exporters/producers subjected with ad duty since the residual duty is applied to all other producers/exporters from China.* The Designated Authority in the present case on the basis of information filed by the applicant found that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation as production of Vitrified/porcelain tiles by HWC was started only after 6<sup>th</sup> June ,2001 i.e, much after the period of investigation

in the original investigation and they were not found to be related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subjected to anti dumping duties. In support of their claim they have filed the certificate of incorporation having the date of commencement of business and the Authority also did not find any adverse material regarding their claim of a new shipper. None of the interested parties filed any material evidence regarding the claim of the entitlement of the new shipper. It has been submitted by the exporter that 14 companies are directly or indirectly related to the producer/exporter. It was explained that out of 14 companies 2 are investment companies, 4 are trading companies and remaining 8 are producing companies. Of the eight producing companies only three companies were producing the subject goods and came into existence only after 31.3.2001 i.e., after period of investigation of the original investigation. Copies of the enterprise business licenses, along with translated version, of the group companies were provided to the verification team. It is noted that any of the group companies would have exported only after 31.3.2001 i.e., after the period of investigation of the original investigation therefore nothing adverse could have been assumed against the claim of the new shipper applicant and no material evidence was brought before the Authority in this regard.

8. Claims with regard to eligibility of the applicant as a new shipper were examined whether the company has directly or indirectly exported the product to India in the original investigation. The producer, HWC was set up on 6<sup>th</sup> June, 2001 and it was claimed that they did not export the product in the original investigation and in support of their claim they filed a copy of business license of the company which shows the date of establishment as 6<sup>th</sup> June, 2001. The team verified invoices relating to acquisition of plant & machinery and copies of the same were obtained. It was found that the company purchased equipment required for production of the product concerned after its date of incorporation. In view of the above, the Authority holds that new shippers could not have directly or indirectly exported the subject goods to India during the earlier period of investigation in the original investigation.

9. During the course of the investigations, it has been observed that M/s Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd., one of the affiliate shareholders of HWC, had filed some information in response to the original investigation. This response was filed through one of the importers vide their letter dated 17<sup>th</sup> Sept., 2001 stating that the company has exported the product concerned to India. It was however found that another letter was also written to the Authority in that investigation itself, after the said letter, stating that this company made no exports in the period being investigated by the Authority. In view of the above, it is noted that NYC had neither exported any material during the period earlier investigated by the Authority nor any evidence of exports by the same was found in this present investigation. It is further noted that the claim of the applicant is consistent with the claim made before the Authority at the time of original investigation when it was claimed that NYC did not export the subject goods in the investigation period of original investigation. During the investigation the Authority neither found any evidence of relationship of new shipper with any of the exporters and producers in China PR who are subjected to anti-dumping duty nor any evidence was brought before the Authority. The Authority, therefore, notes that the New Shipper Review investigation was initiated in line with the provision laid down in Rule 22 of AD Rules.

10. With regard to the argument made by the domestic industry that HWC did not place any evidence in support of their claim that there were no difference between the goods exported to India and to other countries, it is noted that HWC has filed the sales information in the form of Appendix 1 & 2 respectively containing details of sizes/grades on a transaction to transaction basis. They have filed information regarding transaction-to-transaction details of exports to countries other than India also indicating the names of the country. As regards the differences in the number of transaction in responses filed by HWC and Lungo, it is noted that HWC has filed the entire transactions of export during the POI either through Lungo or any other Chinese exporter whereas Lungo has filed information only to the extent of export sales concerning HWC. It is noted that the entire sales data was verified and no discrepancy regarding the number of transaction was found.

11. The Authority also examined whether the applicant's intention is to circumvent the duties by creating "shell" company or by appointing a sole agent of the product and whether the intent of the present exercise was otherwise to circumvent the duties earlier recommended. During the course of the investigation no material evidence was brought to the knowledge of the Authority, which could have otherwise established that the applicant is not entitled for a new shipper review. The domestic industry has argued that the sales contract/order was not provided to the Authority prior to the initiation. The new shipper has rebutted the argument made by the domestic industry stating that the Indian Anti-dumping Rule does not prescribe such provision. On examination of the arguments made by the interested parties, it is noted that Rule 22 is silent on the quantity/volume required for considering the request of a new shipper review investigation, however, the purpose of Rule 22 is to determine the individual dumping margin for a new shipper who has not exported during the period of investigation of the original investigation and not related with any of the exporters/producers subjected to anti dumping duty. In this case the new shipper has exported 3732.48 Sq. Mtr. of vitrified tiles during the period of investigation which constitutes 0.186% of the total sales of the subject goods of the company.

12. It is argued by the domestic industry that the exporter has kept the vital information confidential depriving the opposing interested parties of the right to challenge the information and make the meaningful submissions to the Authority. The Authority notes that Rule 7 of the AD Rules provides for submission of information by the interested parties on confidential basis subject to the condition laid down therein. Certain information which are either business proprietary information or any other information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it. In this review investigation certain business sensitive information has been kept as confidential such as, information pertaining to corporate structure, marketing and selling arrangements, accounting and financial practices, details about the subject goods and other sensitive information disclosure of which would be of significant



competitive advantage to a competitor and would adversely affect the business of the company. The names of the shareholder, percentage of shares, names of suppliers were claimed as confidential since these information were claimed to be business sensitive if made available to the other interested parties. Similarly the business licenses were also claimed confidential as it would give the other interested parties an undue market advantage in planning their market strategy. The information claimed confidential by the interested parties was examined by the Authority as per provision under AD Rules and such information was considered confidential on being satisfied regarding information claimed confidential. The non-confidential summary of the information submitted on a confidential basis is placed in the public file, which is available for the inspection, by all the interested parties in terms of Rule 6 (7) of the Anti Dumping Rules and the domestic industry has obtained the copies of the same.

13. With regard to interpretation of Rule 22 made by the Domestic Industry that the related entities of the applicant were subjected to residual anti dumping duties, making the applicant ineligible for a new shipper review, it is noted that the argument is not maintainable as criteria laid down in the Rule relates to individual dumping determination and not residual anti dumping duty. One of the purposes of Rule 22 is to prevent the exporter/producer whose individual margin of dumping has already been assessed and in the name of creating new entity solely with a view to circumvent the existing duty rate assessed for the exporter/producer. Thereby the restriction would come into operation in cases where such a related company would have obtained an individual margin of dumping in the original investigation to the applicant new shipper under review, therefore, it is necessary to examine whether the related parties had exported the product concern during the original period of investigation. In view of the above, if the interpretation of the Domestic Industry is accepted than none of the producers/exporters will be eligible for individual dumping determination as each and every exporters/producers from that country would be attracting the residual anti dumping duty as determined in the original investigation as all other category.

#### **D. EXAMINATION OF MARKET ECONOMY TREATMENT AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

##### **D.I Views of Domestic Industry**

14. The domestic industry has submitted that China shall be treated as a non-market economy country in terms of Notification No. 28/2001-Cus (NT) and the Authority shall accordingly apply the principles set out in paragraph 8 of Annexure-I to the AD Rules. They claimed that the NME questionnaire responses filed by HWC and Lungo were in the old format and were highly deficient, therefore, their claim of market economy may be rejected.

##### **D.II Views of exporter/producer(New shipper),**

15. The views of exporter/producer(new shipper) have been summarised below;

(i) Both HWC and Lungo have claimed market economy treatment and have submitted evidence in support of their claims. HWC was a wholly foreign owned



enterprise registered as a company under the Company Law of China. It was established on 6.6.2001. HWC was 100% owned by a Macao company named New Zhong Yuan Group Company Ltd. The Macao Company was owned by two individuals, one of them was a permanent resident of Macao and the other was a Macao passport holder. There was no government shareholding in the company. The Board of Directors of the company comprised of 3 individuals - of which one was a Macao citizen and the remaining 2 were Chinese citizens. None of the Directors were nominated by the Govt. of China or any other local government or governmental authority. The Board of Directors was being appointed only by the shareholders of the company.

(ii) Raw materials were purchased by HWC from unrelated suppliers from the open market at market driven prices. The prices were determined or agreed upon between HWC and its suppliers based on market demand. There were no governmental controls over the production of the subject goods or with regard to the procurement of raw materials for production of the subject goods. HWC had purchased utilities like fuel from a privately held company and electricity from a State owned Public Utility Company. Utilities were charged at normal rates without any special or subsidized rates. They have been charged according to the consumption pattern at the prevailing prices charged by the concerned supplying companies.

(iii) Labour was procured from the open market in China and both HWC and Lungo have full powers to recruit and discharge employees. There was no interference from the State regarding appointment, dismissal, etc. The wage rate was determined from time to time after discussing the same with the employees or representatives of employee unions.

(iv) Both HWC and Lungo had independent accounting systems that adhered to the Chinese GAAP. The accounts reflected the costs and revenues. The accounts were kept on accrual basis and the double entry accounting system was followed. The accounts recorded, inter alia, (a) all income and expenses of the company in cash; (b) buying and selling of all materials for the company; (c) companies registered capital and liabilities; and (d) payment time, adjustment and transfer of registered capital of the company. The annual financial statements were required to be submitted to the Board of Directors for approval after being audited by independent auditors within three months from the close of the fiscal year. The accounts of both HWC and Lungo were being audited by practising CPAs every year and the auditors have followed Chinese Independent Auditing Standards in conducting the audit. The Auditors have certified that the annual accounts conform to the accounting standards for business enterprises and the accounting regulations for business enterprises.

(v) HWC had acquired land on 11.6.2001 on a 50 year lease basis from the People's Government of Xiantang, Dongyuan County, Heyuan City by paying appropriate lease rent in advance for the 50 years tenure. The company had acquired additional land on similar terms in the year 2003. HWC had claimed that they have acquired the plant and machinery from private suppliers upon payment of the applicable market prices to the suppliers. HWC had also paid installation/fixing charges for installing the machinery.

(vi) Since HWC and Lungo were established in the year 2001 and 2002 respectively and that they have acquired all the fixed assets from the market subsequent thereto, the

250561/06-6

question of any distortions being carried over from a non-market economy system did not arise.

(vii) Lungo did not have any loans. HWC had an outstanding loan as on 31.12.2003 and the same had been repaid during the early part of 2004 and no loan was outstanding during the period of investigation.

(viii) Foreign exchange rates were credited to foreign exchange account by using actual exchange rates prevailing in the market. There were no restrictions on acquisition of or holding of foreign currencies.

(ix) HWC and Lungo had never entered into any barter or counter trade operations. Both HWC and Lungo were subject to bankruptcy laws and property laws that guarantee legal certainty and stability for the operations of the firms. They have claimed that the company is operating as per market economy conditions as the prices and costs are reflective of market forces, therefore company may be granted MET and normal value may be determined as per para 1 to 6 of annexure-I of AD Rules.

#### **D.III Examination by the Authority**

16. The Designated Authority, as per para 8(2) of Annexure I of the AD Rules for the purpose of determination of Normal Value, proceeded with a presumption that any country that has been determined to be or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three years period preceding the investigation is a non-market economic country. In the past three years WTO members such as EU and USA have treated China PR as a non-market economy country in anti- dumping investigations. In the instance case, China PR has been proposed to be investigated as non-market economy Country.

17. The Authority sent market economy treatment (MET) questionnaires and exporters questionnaires to M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR (Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter). They filed the response in support of their claim of market economy treatment and requested for determination of normal value as per para 1 to 6 of annexure-I of AD Rules on the basis of export of subject goods to countries other than India since there was no domestic sales of subject goods in their home market. In view of their claim of MET treatment, on-the-spot verification was carried out at the premises of the responding producer and exporter. The Chinese producer has claimed individual treatment on the grounds that they are operating under market economy condition irrespective of prevailing economy situation in the country without any direct or indirect State interference or influence in their business activity. Bureau of Fair Trade, Ministry of Commerce, China PR was also sent the MET general questionnaire to provide information regarding tiles industry and Government policy related with that industry but no response was filed by them.

18. In anti-dumping investigations normal value concerning imports originating in China PR, shall be determined in accordance with para 7 & 8 of Annexure I of the AD Rules. The Authority notes that para 7 of Annexure I of AD Rules provides that:

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin."*

Further Para 8 of Annexure 1 of the AD Rules (as amended) provides that:

*"8 (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph(3)*

*(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economic country;*

*Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)."*

19. It is noted that the responding Chinese producer/exporter furnished information/evidence as mentioned in para 8(3) of Annexure 1 of AD Rules to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether

- a) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;

*Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more*

*such firms subject to anti-dumping investigations, the Designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph.*

20. Detailed questions regarding ownership, management, control, determination of commercial and business policies and on financial situation etc. were addressed to the applicant. The responses filed by them were analyzed to determine whether the applicant exercised a degree of independence from the Chinese Government comparable to what would prevail in a market economy country. The Authority sought general and certain specific information with regard to the following parameters from the applicants:-

- Ownership details
- Shareholding patterns
- Information on promoter/holding company/companies
- Constituents of Board of Directors, their legal status and person/party being represented by them.
- Raw Material Inputs and Costs
- the existence or otherwise of any minimum wage stipulation by the State and if the enterprises are free to decide wages as per market demand.
- Production Facilities and Costs
- Loans and subsidies
- Barter Trade/ Counter Trade
- Profit Distribution
- Bankruptcy and property laws
- Exchange rates conversions

21. In order to examine whether there was any degree of State influence or interference over the allocation of resources and decisions of the applicant, whether directly or indirectly, the ownership pattern of the applicant was examined. The claims/counter claims of the interested parties were taken into account and details in this respect were verified. The Authority examined the composition of Board of Directors of these companies, identity of persons in the Board, their functions, other position held by these persons etc. to determine whether there is any interference or involvement of the State in the management and working of the companies. The Authority relied upon the relevant provisions relating to constitution of Board of Directors, Board of Supervision, General Manager, their functions & powers, appointment & dismissal, autonomy of the company in matters of appointment etc and the role which State or State owned/controlled persons/bodies plays, if any, in such companies whether directly or indirectly.

22. HWC was a wholly foreign owned enterprise registered as a company under the Company Law of China. It was established on 6.6.2001. HWC was 100% owned by a Macao company named New Zhong Yuan Group Company Ltd. The Macao Company was owned by two individuals, one of them was a permanent resident of Macao and the other was a Macao passport holder. Macao based investment company was held by two persons and was not involved in selling the subject goods to India during the investigation period of original investigation or in this investigation. NYC, a related company was producing the subject goods in the previous investigation period, however,

the company did not sell the subject goods to India during previous investigation period. The claim of the applicant that none of their affiliates have directly or indirectly exported the subject goods was examined and did not find any evidence of exports during the investigation period of original investigation. As regards the averment made by NYC, China PR in the original investigation, it is found that it was in fact clarified in that investigation period itself that NYC had not sold any material to India in that investigation period and a letter to this effect had been filed in that investigation itself. They provided a copy of approval of NYC for Enterprises with Foreign Trade Rights in the People's Republic of China issued by Ministry of Foreign Economy and Trade Department, to establish that NYC received permission for exports only after original investigation period.

23. It is noted that the company procured electricity from State owned company and water from a private company. Since electricity procurement was from State owned enterprises, the Authority examined the tariff rates at which the company was getting electricity. Sample invoices were collected and tariff paid by the company was ascertained. It was found that the electricity and water have been charged according to the consumption pattern and the prevailing prices charged by the concerned electricity/water supply company.

24. As regards engaging labour, the company claimed that they took all employment decisions. There is full freedom to the company with regard to its mode of hiring employees and they can be fired also on a very short notice. The terms of engagement of labour were generally governed by the labour contract entered between the company and the employee. They claimed that the Chinese Government did not provide any benefit like housing, medical care etc. however, the company provided accommodation and the cost of the same was reflected in the books of accounts as an expense. Salary was paid every month which includes basic pay and incentive for good work, however, deductions were found to have been claimed in respect of insurance and income tax.

25. It was claimed that the raw materials were purchased from the open market and State was not found to be involved directly or indirectly either in procurement or pricing of raw materials. It was also claimed that major suppliers of major raw materials were neither related with the applicant companies nor State owned enterprises. Business licenses of a few raw material suppliers were also verified.

26. The bankruptcy and property laws were examined and found that the company is free to acquire property. The company claimed that bankruptcy law is applicable to a firm when a firm becomes bankrupt and the details regarding the settlement of the dues is governed by law maintained under bankruptcy law.

27. Even though the producer in the present investigations is HWC, the Authority found appropriate to examine the claim of market economy treatment to Lungo (exporter) also. Business license of the company was examined and it was found that the company is a private company and established on 25<sup>th</sup> June, 2002 i.e., after the period of investigation of the original investigation. On examination of annual reports of Lungo for the years 2003 and 2004, it was found that the company maintained its accounts as per

generally accepted accounting principles of China PR and there was no adverse qualification by the auditors.

28. HWC is a fully foreign owned enterprise by New Zuang Yuan Group Company Ltd, a company incorporated in Macao. It was found that the Macao Company was owned by two individuals - one of them was a permanent resident of Macao and the other was a Macao passport holder. In so far as Lungo was concerned, it was owned by Guangdong New Zhong Yuan Ceramic Company Ltd (90%) and Mr. Zeng Chi Hong (10%). The first shareholder was a Chinese company registered as a limited liability company under the Chinese Company law. The Authority neither found any evidence of State ownership in HWC and Lungo nor any evidence was brought by any interested parties to show the State involvement in these companies.

29. The Authority examined the composition of the Board of Directors of HWC and Lungo and there was no evidence to suggest the State interference in the decision making of the company. The Board of Directors was responsible for all the operational decisions of the company. In terms of Article XIII of the Memorandum of Association of HWC and Lungo, the Board of Directors was the supreme authority of the company to decide all significant issues of the company. The Board was also responsible for appointing senior staff including General Manager of the Company, complement or modify the Memorandum and Articles of the Company, discuss the closure or liquidation of the company, approve the financial statement, income and expenses budget and annual profit distribution plan and decide to approve all important reports submitted by the General Manager of the company.

30. HWC was engaged in the production of subject goods and other goods and it came into existence on 6.6.2001. The land was acquired in 2002 and the plant was established thereafter. The company has an installed capacity of 6125382 sq. metres and the actual production during IP was 2287468 sq. metres. It was found that HWC was selling the subject goods through related or unrelated companies in China, who in turn exported the subject goods.

31. The Authority did not find any restrictions on the sale or disposal of the finished goods or on the quantity or prices at which the subject goods could be sold or purchased or exported.

32. It was also found that the accounts reflected the costs towards depreciation of plant, machinery and other fixed assets. Both HWC and Lungo were found to be maintaining monthly profit and loss statements. It was found that monthly profit and loss statements alongwith VAT returns were filed with the concerned Chinese Government authorities. HWC did not earn any profit and therefore, no dividends were distributed. Lungo had earned nominal profits but the Board of Lungo did not recommend distribution of dividend so far. VAT refund application made by Lungo was examined and it was found that the VAT refund has been claimed by the company. It is noted that the company is entitled for a 13% VAT refund for their exports of subject goods made during the period of investigation. Thus, it is noted that any significant State interference with regard to prices, costs and inputs including raw materials, costs of technology, labour, output, sales and investment, etc. was not found.

33. It was found that some of the equipments had been imported from SITI Italy through SITI China PR. Wherever the equipments had been purchased locally, it was found that they have been procured on payment. It was found that the company had paid for the value of the land and also the other fixed assets. The company's accounts showed the charges towards amortization of land and depreciation of other fixed assets.

34. HWC came into existence only on 6.6.2001, and the evidence on record did not show any effects or distortions from the former non-market economy system. Similarly any evidence regarding barter trade and/or payment via compensation of debts was also not found. It was found that both HWC and Lungo were found to be free to acquire property. HWC and Lungo claimed that the bankruptcy law would be applicable to them in the event they become bankrupt and it was found that the Chinese property laws and bankruptcy laws guarantee certainty and stability for the operations of the firms.

35. The exchange rate conversions were also verified from their books of accounts and found that the export remittance were converted into the Chinese currency as per the exchange rate prevailing on the date of transaction. During the verification visit the export invoices were verified to see whether the realized amounts are credited into their books of accounts. The Authority observed that exchange conversions have taken place at the existing rate, which was more or less stable.

36. In view of the information provided by the Chinese producer and exporter on the issue of its claim of market economy treatment with regard to para 8(3) of Annexure-I of AD Rules, the Authority considers it appropriate to treat this company as operating in market economy since they were able to show to the satisfaction of the Authority that management and control regarding production, marketing and pricing were in the hands of the management of the company, which were found to be independent from state intervention. In the light of above examination it was considered to grant Market Economy Treatment to the company and determine normal value as per para 1 to 6 of Annexure 1 to the Anti Dumping Rules.

#### **NORMAL VALUE**

37. Under Section 9A(I)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

38. The Authority sent exporter questionnaire to M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter), for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1) (c) of the Custom Tariff Act. In response to the questionnaire the new shipper filed the information in exporter questionnaire. For computation of normal value in respect of similar models/size of vitrified tiles exported to India, it was observed that the company did not have any domestic sales, therefore, the sales to the appropriate third country were examined and it was not found to be in the ordinary course of trade since these exports were made at loss. Accordingly the cost of production of the exporter with reasonable profit margin has been considered to be appropriate for determination of normal value. They have also provided break up of costs of production in prescribed format of all the sizes/models/types of the subject goods that have been produced during the period of investigation. The element wise cost of production was also verified and reconciled from the books of account maintained by the company. The cost of production based on the verified data for the product was considered for determination of normal value. Since no appropriate trend of reasonable profit could be established, profit @5% on the cost of production has been considered reasonable to assess the constructed normal value.

39. The company has exported only 600x600 size of Vitrified Tiles to India during the period of investigation. Based on the methodology explained above constructed normal value has been determined as RMB \*\*\*\*/Sq.Mtr.

### **EXPORT PRICE**

40. In response to the questionnaire, the exporter has furnished invoice-wise/ size-wise details of exports made to India during the period of investigation in Appendix-2. The exporter has also furnished copies of invoices in support of the same. The sales of the goods from HWC to Lungo were verified from their original records and exports of subject goods from Lungo to ET were also verified. The company has exported 3732.48 Sq. Mtr. of vitrified tiles to India during the period of investigation. Adjustment claimed by the exporter in Appendix-3 have been considered to arrive at the ex-factory export price to India. The exports to India by Lungo through ET were verified and it was found that the subject goods were exported at the F.O.B level. It was found that the aggregate amount of the export sales have been realized vide Bank advice issued by China Industrial & Commercial Bank. The ex-factory export price of subject goods has been determined as RMB \*\*\*\*/Sq Mtr.



**DUMPING MARGIN:**

41. Considering the normal value and export price as determined above, dumping margin has been determined. It has been found that the exporter has exported the subject goods above its Normal Value and hence the dumping margin has been determined as negative.

**E. Final Findings and Recommendations of the Authority**

42. After considering the foregoing the Authority concludes that;

i) Export price of Vitrified/porcelain Tiles exported to India produced by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter), of Guangdong, China PR is above its normal value during the period of investigation.

ii) The Authority, therefore, recommends that no anti dumping duty be imposed on imports of Vitrified/porcelain Tiles falling under Chapter 69 of the Custom Tariff Act, 1975 produced by M/s. Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd., China PR(Producer) and M/s. Foshan Lungo Ceramics Co., Ltd., China PR (Exporter) through M/s. Enterprise Trading FZE, UAE (Exporter).

iii) An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority